● जयपुर, रविवार 15 दिसंबर 24 ● वर्ष 14 ● अंक 117 ● पृष्ठ : 8 ● मूल्य : 1 रुपये
www.chamaktarajasthan.in | Email : chamaktarajasthan8789@gmail.com

डाक पंजीयन संख्या: RJ/JPC/D19/2024-25
RNI. No. RAJHIND/2011/40950

दैनिक राज्य तथा केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त
सच के साथ मजबूती से बढ़ाये क़दम

चमकता राजस्थान

विज्ञापन के लिए : 93145 05000
जयपुर से प्रकाशित एवं प्रसारित
अजमेर, सीकर, झुंझनुं, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, धौलपुर, हिंडौन, भरतपुर, झालावाड़, जोधपुर, बीकानेर से प्रसारित

सुविचार
''सत्य को हज़ार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा।''
● स्वामी विवेकानंद

पेज @3 उप महानिरीक्षक पुलिस जयप्रिा कैलाश चन्द विश्नोई ने नवीन अवैध कॉलोनियों पर कसा...
पेज @4 जयपुर ज्वैलरी शो 2024 अपने 22वें वर्ष में 20 दिसंबर से 23 दिसंबर, रहेगी...
पेज @8 राज्य में सड़कों की गुणवत्ता को लेकर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी गंभीर...

सुरक्षा के लिए ऐप लॉन्च किया; बसों में मिलेगा पैनिक बटन

प्रदेश भाजपा सरकार का एक वर्ष राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन

कंधे से कंधा मिलाकर चल रही महिलाएं : मुख्यमंत्री शर्मा

राज्स सरकार का एक वर्ष मातृ शक्ति के सम्मान सुरक्षा और कल्याण को समर्पित :- उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी

चमकता राजस्थान

उदयपुर। उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा- इतनी बड़ी संख्या में माताएं-बहनें आई हैं उन्हें नमस्कार करता हूं। उन्होंने कहा जहां नारियों का सम्मान होता है वहां हमेशा देवताओं का निवास होता है। हम पुरुष-स्त्री को रथ के दो पहिए के समान देखते हैं। पहले कहा जाता था कि हर सफल पुरुष के पीछे महिला होती है। अब कहा जाना चाहिए कि हर सफल व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली महिला शक्ति होती है। सीएम ने कहा- पिछली सरकार के समय महिला अपराध से राजस्थान बदनाम रहा था। हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा था कि महिला अपराध को लेकर कार्रवाई करेंगे।हमने सरकार बनते ही इस पर काम शुरू कर दिया। महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ रोकने के लिए रात के समय पेट्रोलिंग शुरू की। हमने महिला सुरक्षा के लिए ऐप भी शुरू किया है। हमारा प्रयास है कि बालिकाओं को शुरू से ही शिक्षा प्राप्त हो ताकि वह उन्नति की और अग्रसर हो। हम इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए लाड़ो प्रोत्साहन योजना शुरू की है। आज हमने 1 लाख लाभार्थियों को राशि भेजी है। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने निशुल्क स्कूटी छात्राओं को प्रदान की। उन्होंने शिक्षा विभाग की लाभार्थी बालिकाओं के साथ फोटो खिंचवा कर उनको प्रोत्साहित किया। सीएम ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्टाल पर महिलाओं को इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम देने की जानकारी ली और लाभार्थियों संवाद भी किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा, टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राज्यमंत्री मंजू बाघमार भी मौजूद रही।

संविधान का दुरुपयोग कांग्रेस के डीएनए का हिस्सा : प्रधानमंत्री

नयी दिल्ली। एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि संविधान का दुरुपयोग करना और उसकी भावना को खत्म करना, कांग्रेस के डीएनए का हिस्सा रहा है और हमारे लिए संविधान, उसकी पवित्रता और अखंडता सबसे महत्वपूर्ण है। यह केवल शब्द नहीं है बल्कि कसौटी के समय में हमने करके दिखाया है और हम तप करके निकले हुए लोग हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए सत्ता का सुख और सत्ता की भूख यही एकमात्र इतिहास है। कांग्रेस ने इसके लिए संविधान संशोधन किए हैं लेकिन हमने देश की एकता, अखंडता और उज्ज्वल भविष्य के लिए संविधान में संशोधन किये हैं और संविधान की भावना के

कहा, हमारे लिए संविधान की पवित्रता और अखंडता सर्वोपरि

प्रति पूर्ण समर्पण के साथ किए हैं। प्रधानमंत्री ने आज संविधान की 75 वर्ष की गौरव यात्रा पर लोकसभा में आयोजित चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि उनकी सरकार संकल्प से सिद्धि के मंत्र पर काम कर रही है और मानती है कि देश की एकता ही इसका आधार है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने देश की विविधता का उत्सव मनाने की बजाय इसमें जहरीले बीज बोने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने एक परिवार को आगे पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस एक परिवार का 55 वर्षों तक देश में शासन रहा है और उसकी कुरीति और कुनीति की परंपरा आज भी चल रही है। कांग्रेस ने संविधान को हर स्तर पर चुनौती दी है। 1951 में अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करते हुए अध्यादेश लाने से यात्रा शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुंह में संविधान का शिकार करने का खून लग गया था और समय-समय पर उसने संविधान संशोधन किया और संविधान की भावना को लहूलुहान किया।

मोदी का 11 संकल्प लेने का आग्रह

1- चाहे नागरिक हों या सरकार हो सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें।
2- हर क्षेत्र हर, हर समाज को विकास का लाभ मिले यही है सबका साथ सबका विकास है।
3- भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस हो भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता नहीं हो।
4- देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपरा के पालन में देश के नागरिकों को गर्व हो।
5- गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और राष्ट्र की विरासत पर गर्व हो।
6- देश की राजनीति को परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति मिले।
7- संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए।
8- संविधान की भावना के अनुसार जिनको आरक्षण मिल रहा है उसे न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण पर रोक लगे।
9- भारत महिलानीति विकास के मामले में दुनिया के लिए आदर्श प्रस्तुत करे।
10- राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास की भावना से काम करें।
11- एक भारत श्रेष्ठ भारत ध्येय हो।

करीब पौने दो घंटे के भाषण के अंत में कहा कि उन्हें देश की जनता, देश की महिलाओं और युवाओं की क्षमता पर भरोसा है और यदि देश इन संकल्पों के साथ चले तो संविधान के 100वां वर्ष पूरा होने तक कोई हमें विकसित राष्ट्र होने से रोक नहीं सकता।

हमारा संविधान सबसे बड़ा और खूबसूरत : किरण रिजिजू

- हमारे देश में अल्पसंख्यक आयोग है, अन्य देश में नहीं
- देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित, तभी दूसरे देशों के पीड़ित आते हैं

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने समानता को संविधान की आत्मा करार देते हुए लोकसभा में आज कहा कि इसमें सभी नागरिकों के लिए बराबरी का अधिकार और अवसर प्रदान किया गया, इसलिए यह दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत संविधान है।

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 'संविधान अंगीकार करने के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा' पर आज दूसरे दिन चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि संविधान की भावना के अनुसार ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ सरकार का कामकाज शुरू किया। उन्होंने कहा कि संविधान की बदौलत ही आज देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला विराजमान है। उनूहोंने कहा कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं, बल्कि सबसे खूबसूरत भी है, जिसमें सभी के लिए प्रावधान है। इस संविधान को लेकर हम लोग गौरव महसूस करते हैं।

रिजिजू ने कहा कि हमारे देश में अल्पसंख्यक आयोग है, जबकि अन्य देश में ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कानून बनाया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं बनाई गई, जिसका उनको लाभ मिल रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की रिपोर्ट

दुनिया भर में हर घंटे डूबने से 30 से अधिक लोगों की मौत

जिनेवा/नयी दिल्ली। एजेंसी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने डूबने से मरने वालों की रोकथाम पर अपनी पहली रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें 2000 के बाद से विश्व में डूबने से होने वाली मृत्यु दर में 38 प्रतिशत की गिरावट आयी है, लेकिन कम आय वाले देशों में यह जोखिम ऊंचा बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डूबना एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, जिसमें अनुमान है कि हर घंटे 30 से अधिक लोग डूब रहे हैं और अकेले 2021 में तीन लाख लोगों की डूबने से मौत हुई। करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत 29 वर्ष से कम उम्र में हुई है और एक चौथाई मरने वाले पांच वर्ष से कम उम्र के

डूबने वालों में आधे 29 साल से कम उम्र के

बच्चे होते हैं। वयस्कों की देखरेख के बिना बच्चों में डूबने का जोखिम विशेष रूप से अधिक होता है।

डब्ल्यूएचओ ने डूबने से मौत की गिरावट को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि यदि मौजूदा रुझान जारी रहे, तो वर्ष 2050 तक 72 लाख से अधिक लोग, मुख्य रूप से बच्चे डूबने से मर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि उसके द्वारा सुझाए गए हस्तक्षेपों को लागू करके डूबने से होने वाली अधिकतर मौतों को रोका जा सकता है। डब्ल्यूएचओ डूबने से होने वाली मौत की रोकथाम के लिए समुदाय-आधारित कार्रवाइयों की एक श्रृंखला की सिफारिश की है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस ने कहा, 'वर्ष 2000 से डूबने से होने वाली मौतों में उल्लेखनीय गिरावट सुखद है और यह इस बात का सबूत है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा सुझाए गए सरल, व्यावहारिक हस्तक्षेप कारगर साबित हो रहे हैं।' रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर, डूबने से होने वाली 10 में से नौ मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। अफ्रीकी क्षेत्र में डूबने से प्रति एक लाख लोगों में 5.6 मौतों का औसत किसी अन्य क्षेत्र की तुलना में सबसे अधिक दर है। अफ्रीकी क्षेत्र में केवल 15 प्रतिशत देशों के पास डूबने की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रणनीति या योजना थी, जबकि यूरोपीय क्षेत्र के 45 प्रतिशत देशों के पास थी। डब्ल्यूएचओ डूबने की रोकथाम के लिए समुदाय-आधारित कार्रवाइयों की एक श्रृंखला की सिफारिश की है। इनमें बच्चों को पानी तक पहुंचने से रोकने के लिए अवरोधों की स्थापना, विद्यालय जाने की उम्र से पहले के बच्चों के लिए पानी से दूर सुरक्षित स्थानों का प्रावधान, स्कूली बच्चों को बुनियादी तैराकी जल सुरक्षा और सुरक्षित बचाव कौशल सिखाना, लोगों को बचाव और पुनर्जीवन में प्रशिक्षण देना, डूबने के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को मजबूत करना, सुरक्षित नौकायन, शिपिंग और नौका विनियम स्थापित करना और लागू करना, और बाढ़ जोखिम प्रबंधन में सुधार करना जैसी सिफारिशें शामिल हैं।

उत्तर भारत में शीत लहर, सुबह-शाम कोहरा छाए रहने का अनुमान

नयी दिल्ली। एजेंसी

मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लिए अगले दो-तीन दिनों तक शीत लहर जारी रहने की संभावना जताई है। इसके साथ पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है, जिसका असर मैदानी इलाकों में पड़ सकता है। शनिवार को मौसम विभाग ने बताया कि राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगले दो दिन न्यूनतम तापमान सामान्य से एक से दो डिग्री कम रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब के कुछ स्थानों पर शीत लहर से लेकर गंभीर शीत लहर की स्थिति देखी गई है।

जम्मू-कश्मीर में हो सकती है बर्फबारी

राज्य में पड़ रही कड़ाके की ठंड, लगातार चल रही हवा ने बढ़ाई परेशानी

रांची/एजेंसी। राज्य में लगातार बह रही उत्तरी-पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी रांची में शनिवार को सुबह कोहरा छाया रहा। दिन ढलने के बाद आसमान साफ हो गया लेकिन ठंड के असर में कोई कमी नहीं देखी गयी।

कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रतिबंध

सोशल मीडिया लोगों के बीच बातचीत के ऐसे माध्यम को संदर्भित करता है, जिसके ज़रिए वे वर्चुअल समुदायों और नेटवर्क में जानकारी और विचारों का निर्माण, साझा और/या आदान-प्रदान करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऐसे कानून पेश करने की घोषणा की है, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने से रोकेगा। यह स्पष्ट है कि हमें बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन बेहतर तरीके से सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग का मानना है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना सही नहीं है। ऐसे प्रतिबंधात्मक विकल्प उपलब्ध हैं, जो बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन नुकसान से बचाने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाने और सभी के लिए ऑनलाइन सुरक्षा में सुधार का तरीका निकाला जा सकता है। सोशल मीडिया बच्चों और युवाओं को साइबरबुलिंग, हानिकारक सामग्री और ऑनलाइन शिकारियों सहित कई संभावित जोखिमों के संपर्क में लाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग स्वस्थ मस्तिष्क विकास, नींद और शैक्षणिक प्रदर्शन में बाधा डाल सकता है। प्रस्तावित कानून एक सुरक्षित विकासात्मक वातावरण का समर्थन करता है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं से बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा एकत्र करते हैं और बच्चे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि उनका डेटा कैसे एकत्र किया जाता है, उपयोग किया जाता है या उसका मुद्रीकरण किया जाता है। युवा उपयोगकर्ताओं के लिए पहुँच पर प्रतिबंध लगाने से गोपनीयता के उल्लंघन और बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के शोषण को कम करने में मदद मिल सकती है।

पहुँच को प्रतिबंधित करने से माता-पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को बेहतर ढंग से निर्देशित करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि वे पर्यवेक्षित तरीके से तकनीक से जुड़ें। हमें बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन स्पेस को बेहतर तरीके से नेविगेट करने में मदद करने की भी आवश्यकता है, यह सुनिश्चित कर-के कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा सिखाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। युवाओं को इस बारे में गंभीरता से सोचना सिखाया जाना चाहिए कि वे ऑनलाइन क्या देखते हैं और वे सोशल मीडिया से कैसे जुड़ते हैं। माता-पिता और शिक्षकों को उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने में मदद करने के लिए बेहतर उपकरणों और संसाधनों की भी आवश्यकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स व्यक्तियों और संगठनों को पारंपरिक प्रचार या शैक्षणिक तरीकों से बेजोड़ गति से जानकारी साझा करने और आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं। सोशल मीडिया ने लोगों के बीच जानकारी साझा करने के तरीके को बदल दिया है। नतीजतन, यह निर्णय लेने में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके सुशासन को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया के फायदों में से एक यह है कि यह सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है। सोशल मीडिया ने नागरिकों और उनकी चुनी हुई सरकार और राजनेताओं के बीच की खाई को कम किया है, जिससे लोकतंत्र में अधिक भागीदारी हुई है।

गलत सूचना के प्रसार का मुद्दा सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान बनकर उभरा है। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग मस्तिष्क के उन हिस्सों को बदल सकता है जो भावनाओं और सीखने से सम्बंधित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021. सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत निवारण और अनुपालन तंत्र स्थापित करने के लिए कहा गया है, जिसमें एक शिकायत अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों और की गई कार्यवाही पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को संदेश के पहले स्रोत को ट्रैक करने के लिए प्रावधान करना होगा।

धारा 79 में कहा गया है कि किसी भी मध्यस्थ को उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध या होस्ट की गई किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या संचार लिंक के लिए कानूनी रूप से या अन्यथा उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। यदि मध्यस्थ, सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा सूचित या अधिसूचित किए जाने के बावजूद, प्रश्नगत सामग्री तक पहुँच को तुरंत अक्षम नहीं करता है, तो सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। एक व्यापक पारदर्शिता कानून की आवश्यकता है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा प्रासंगिक खुलासे को अनिवार्य बनाता है। इसके अतिरिक्त, सामग्री मॉडरेशन और सम्बंधित कार्य जैसे मानक सेटिंग, तथ्य-जांच और डी-प्लेटफ़ॉर्मिंग को शामिल किया जाना चाहिए। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के सम्बंध में माता-पिता को अपने बच्चों को डिजिटल उपकरणों तक पहुँच प्रदान करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए तथा उनके साथ स्वस्थ उपयोग के बारे में चर्चा करनी चाहिए।

विपक्षी दल मतदाताओं से हार जाते हैं, दोष ईवीएम को

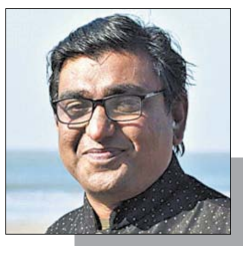

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

पहले, गांधी परिवार की कांग्रेस के लिए हर चुनाव में भारी बहुमत पाना सहज प्रक्रिया थी, लेकिन अब राहुल गांधी और अन्य वंशवादी दलों के लिए चुनाव जीतना एक दुःस्वप्न बन गया है। बढ़ती साक्षरता दर, राष्ट्रीय चिंताओं की बढ़ती समझ और कांग्रेस का असली चेहरा हमारे अद्भुत देश के लोगों को दिखाई दे रहा है। हालांकि, गांधी परिवार और वंशवादी राजनीतिक दल वास्तविकता को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। वे मानते हैं कि राज्यों और राष्ट्र पर शासन करना उनका जन्मजात अधिकार है और जब 2014 के बाद से ऐसा नहीं हुआ है, तो वे तथ्यों पर विचार किए बिना तकनीकी रूप से बेहतर चुनावी प्रक्रियाओं और सरकारी संस्थानों को दोष देते हैं। महाराष्ट्र के मारकड़वाड़ी गांव में मतपत्र से मतदान को लेकर जो नाटक हुआ, वह डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान का अपमान है। किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति को स्वार्थी कारणों से संविधान का अनादर करने का अधिकार नहीं है।

ईवीएम हैक क्यों नहीं किया जा सकता

अगर ईवीएम हैकिंग संभव है, तो क्या सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली शक्तिशाली कांग्रेस ने पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुमत से जीतने दिया होता? अगर ईवीएम हैकिंग संभव है तो भाजपा, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 या उससे अधिक सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही थी, उसे केवल 240 सीटें ही क्यों मिलीं, जो 272 सीटों के साधारण बहुमत से भी कम है? अगर ईवीएम हैकिंग संभव है, तो भाजपा केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब और जम्मू कश्मीर में इतने बड़े अंतर से क्यों हारी। ये भाजपा के जीतने के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। तार्किक रूप से, अगर हम इन सभी तर्कों पर विचार करते हैं, तो इंडी गठबंधन की झूठी कहानी विफलता को स्वीकार करने में असमर्थ प्रतीत होती है।

ईवीएम को अपनाना क्यों था आवश्यक

1990 के दशक के दौरान चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने मतपत्र धोखाधड़ी से निपटने के महत्व को पहचाना। उन्होंने संभावित उत्तर के रूप में ईवीएम के विकास पर जोर दिया। जबकि राजनीतिक दलों ने चिंता व्यक्त की थी, लेकिन ईवीएम से छेड़छाड़ का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। हालांकि, समस्या बनी हुई है। ईवीएम की शुरुआत से पहले, भारतीय चुनावों में वोट डालने के लिए मतपत्रों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। मतपत्रों का उपयोग समय लेने वाला था, बूथ कैप्चरिंग और मतपेटी में बदलाव जैसी गड़बड़ियों का खतरा था, गलत मार्किंग के कारण बड़ी संख्या में

अवैध वोट होते थे, लंबी गिनती की कवायद, अधिक विवाद और देरी से परिणाम की घोषणा होती थी और यह एक पर्यावरण को हानि करने वाला और गैर-पर्यावरणीय तरीका था। 2017 में जब भारत के चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से ईवीएम मशीनों की हैकिंग या छेड़छाड़ साबित करने को कहा तो कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं कर पाया, जिससे यह साबित हो गया कि चुनाव हारने के बाद इंडी गठबंधन द्वारा लगाए गए आरोप महज मतदाताओं को धोखा देने और डॉ बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में विश्वास की कमी पैदा करने का नाटक है। पहले, कागज मोड़ने और मतदाताओं द्वारा अपने स्टांप की जगह को थोड़ा बदलने के कारण कई वोट रद्द हो जाते थे। कई अनपढ़ व्यक्ति या कांपते हाथों ने अपने स्टांप को बॉक्स की सीमा पर या बाहर थोड़ा धकेल दिया, जिससे वोट अवैध हो जाते थे। विभिन्न स्थानों पर राजनीतिक गुंडों और असामाजिक तत्वों ने बॉक्सों की अदला-बदली की। गिनती एक मैनुअल प्रक्रिया का उपयोग करके हुई, जिससे गलत गिनती की संभावना बढ़ जाती थी।'

ईवीएम के महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य लाभ

-ईवीएम के साथ मतदान करना काफी सरल और मतदाता-अनुकूल है क्योंकि मतदाता को अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने के लिए केवल बीयू पर बटन दबाने की आवश्यकता होती है।

-ईवीएम प्रणाली में कोई भी अवैध वोट नहीं होता है, हालांकि बैलेट पेपर प्रणाली के साथ, काफी संख्या में बैलेट पेपर अवैध हो जाते थे, और कुछ परिस्थितियों में, अवैध बैलेट पेपर की संख्या निर्वाचित उम्मीदवार के जीत के अंतर से अधिक हो जाती थी।

-यह ऑडिट करने योग्य, पारदर्शी, सटीक, सुरक्षित है, और मानवीय त्रुटि को कम करता है।

-यह कुछ घंटों में तेज परिणाम प्रदान करता है, जो कि भारत जैसे विशाल देशों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां कई सौ हजार मतदाता हैं, जहां गिनती में कई दिन या हफ्ते लगते थे।

-ईवीएम मतदान से समय, ऊर्जा और धन की भी बचत होती है, लाखों पेड़ों की तो बात ही छोड़िए। पहले, करोड़ों बैलेट पेपर छापे जाते थे, जिसके लिए सैकड़ों टन कागज की जरूरत होती थी, और बैलेट पेपर का उत्पादन बहुत लंबे समय तक बड़ी संख्या में सरकारी प्रेस में किया जाता था, जिसके लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सैकड़ों चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाते थे।

-इसके अलावा, देश में मतदान के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रगति का अभिनव उपयोग भारतीय समाज की रचनात्मकता, आविष्कारशीलता और अग्रणी कौशल का पूर्ण समर्थन करता है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की छवि और प्रतिष्ठा को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। जैसा कि स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, मतपत्रों और ईवीएम दोनों के साथ 7 दशकों से अधिक समय तक चुनाव कराने में संचित तुलनात्मक अनुभव का भार, साथ ही ईवीएम का उपयोग करने के कई स्पष्ट लाभ, ईवीएम को वोट डालने का पसंदीदा तरीका बनाते हैं।

मतपत्रों का उपयोग स्पष्ट रूप से एक पारंपरिक, पुरातन मतदान प्रक्रिया थी। मतपत्रों का उपयोग करने की पिछली प्रथा के साथ उपरोक्त मुद्दों को संबोधित करने के साथ-साथ तकनीकी सुधारों को बनाए रखने के लिए, ईसीआई ने 1977 में ईवीएम का विचार प्रस्तावित किया।

ईवीएम पर विभिन्न न्यायालयों की प्रतिक्रिया

कर्नाटक उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय दोनों ने कहा कि चुनावों में ईवीएम का उपयोग करने से पारंपरिक बैलट पेपर/बैलेट बॉक्स चुनाव प्रणाली की तुलना में महत्वपूर्ण लाभ हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने ईवीएम से छेड़छाड़ के किसी भी आरोप को स्पष्ट रूप से नकार दिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं : 'वायरस अंदर जाने का कोई जोखिम भी नहीं है क्योंकि ईवीएम की तुलना व्यक्तिगत कंप्यूटर से नहीं की जा सकती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ईवीएम से कोई लेना-देना नहीं है। कंप्यूटर में अपने इंटरनेट कनेक्शन के कारण अंतर्निहित सीमाएं होंगी और डिजाइन के अनुसार, यह प्रोग्राम संशोधन की अनुमति दे सकता है, लेकिन ईवीएम स्वायत्त इकाइयां हैं और ईवीएम में प्रोग्राम मौलिक रूप से अलग है।'

महाराष्ट्र परिणाम

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में हाल ही में इंडी गठबंधन द्वारा लगाए गए आरोपों की कई स्थानों पर जांच की गई है, जैसा कि हारे हुए उम्मीदवार ने मांग की थी, और वीवीपीएटी पर्चियों और डाले गए वोटों का मिलान बिल्कुल सही पाया गया है। हालांकि, राहुल गांधी, शरद पवार और अन्य इंडी गठबंधन के नेता अभी भी हार को पूरी तरह से स्वीकार किए बिना इसे मुद्दा बना रहे हैं। हमारे देश के लोग ऐसे किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं करेंगे जो पूरी तरह से फर्जी हो और संविधान का उल्लंघन करता हो। यह समय है कि गांधी परिवार और अन्य राजवंशों को केवल वोट बैंक के बजाय लोगों के कल्याण के लिए वास्तव में चिंतन और प्रयास करना चाहिए। झूठे आख्यानों का उपयोग करने के बजाय ऊर्जा को निर्देशित करने का यह सबसे प्रभावी तरीका है। आइए हम मतदाताओं की बुद्धिमत्ता पर विश्वास करें और लालची जरूरतों के लिए काम करना बंद करें।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

भारत में संसद पर हमले की बरसी, सुरक्षा, पीड़ितों की स्थिति और सरकार के प्रयास

कैलाश केशरी

13 दिसंबर 2001 का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काले दिन के रूप में याद किया जाता है। इस दिन भारतीय संसद भवन पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें भारतीय लोकतंत्र की हृदयस्थली पर एक गंभीर खतरा मंडराया। उस हमले में संसद के भीतर मौजूद सांसदों और सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों और त्वरित कार्रवाई के कारण बड़ी जनहानि से बचाव हुआ। हमले में आहत हुए कुछ सांसदों और सुरक्षा कर्मियों को शारीरिक चोटें आई, जबकि मानसिक आघात ने कई अन्य लोगों को प्रभावित किया। इस हमले के बाद भारत सरकार ने संसद और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों की सुरक्षा को लेकर कई अहम कदम उठाए थे। संसद भवन की सुरक्षा को और अधिक कड़ा किया गया है। अब संसद भवन में प्रवेश के समय सुरक्षा जांचों को और सख्त कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई है और उन्हें अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकों से लैस किया गया है। दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) जैसी सुरक्षा एजेंसियों को संसद की सुरक्षा में और भी प्रभावी तरीके से लगाया गया है। इस हमले के बाद भारतीय सुरक्षा व्यवस्था में गहरी सोच और बदलाव आया है, जिसमें आतंकवाद के प्रति न केवल शारीरिक सुरक्षा बलों को तैयार करनाए बल्कि आतंकवादियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए गुप्तचर एजेंसियों को भी सक्रिय किया गया।

सरकार ने आतंकवाद को रोकने के लिए कई कदम उठाएए जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) जैसे कड़े कानूनों का सहारा लिया गया। इसके तहत

आतंकवादियों और उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए समुचित कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की गई। सीमा पर सुरक्षा को भी काफी बढ़ा दिया गया हैए ताकि कोई भी आतंकवादी संगठन भारत की तरफ बढ़ने में सफल न हो सके।

संसद पर हमले के बाद आहत सांसदों और सुरक्षाकर्मियों को सरकार ने कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान कीं। उनके इलाज का पूरा खर्च सरकार ने उठाया और पुनर्वास के लिए उन्हें उचित आर्थिक सहायता दी गई। कुछ सांसदों को गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन उनका इलाज समय पर किया गया। जिन लोगों ने शारीरिक और मानसिक रूप से इस हमले को झेला, उन्हें सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य सहायता भी मुहैया कराई। इसके अलावा, कुछ सांसदों को पेंशन और अन्य लाभ प्रदान किए गए ताकि उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत रहे। वर्तमान में सरकार सुरक्षा के मामलों में और भी सख्त कदम उठा रही है। संसद भवन की सुरक्षा के लिए अब एक गहरी और व्यापक रणनीति तैयार की गई है। संसद में प्रवेश करने से पहले, प्रत्येक व्यक्ति की कड़ी जांच की जाती है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही, भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, सभी प्रमुख सरकारी संस्थानों, जैसे संसद, राष्ट्रपति भवन और अन्य संवेदनशील जगहों की सुरक्षा में और सुधार किए गए हैं।

भारत सरकार आतंकवाद के प्रति अपने दृष्टिकोण को और कठोर बनाते हुए, हमले के बाद के वर्षों में कई महत्वपूर्ण सुधारों के साथ आ रही है। अब सिर्फ शारीरिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि आतंकवाद के मानसिक और आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है। आतंकवादियों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए गुप्तचर एजेंसियों का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है और सरकार लगातार इस बात पर काम कर रही है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

आज संसद भवन की सुरक्षा में जहां एक ओर कठोरता और सतर्कता बरती जा रही हैए वहीं संसद पर हुए हमले में आहत हुए सांसदों और सुरक्षाकर्मियों को सरकार की ओर से दी गई सहायता ने उन्हें इस कठिन समय से उबरने में मदद की है। हमले के बाद सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ऐसे हमलों से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मुकाबला किया जाए और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।

संसद पर हमले के इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए हम यह भी देख सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र ने किस तरह इस हमले को झेला और फिर से अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। हमले में आहत लोग अब इस कठिन समय से उबर चुके हैंए लेकिन यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर सतर्कता, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की आवश्यकता है।

कोलकाता जैसे तेजी से बढ़ते शहरों में शहरी नियोजन की असंख्य चुनौतियां

मनतार सिंह

वर्तमान में भारत में शहरों का नियोजन का कार्य बहुत ही जटिल होता जा रहा है। विशेषकर कोलकाता जो भारत के सबसे पुराने महानगरीय शहरों में से एक के रूप में पहचान बना चुका है। कोलकाता शहर एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास से परिपक्व है। ब्रिटिश शासन काल से ही यह शहर दूसरे शहरों से कहीं अधिक तेजी से उन्नति की ओर अग्रसर था। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1950 में कोलकाता की जनसंख्या 46 लाख थी और फिर आधुनिकीकरण, जनसंख्या के बोझ और शहरी विकास के दबाव से जूझ रहा है, यह शहर यहां पर नियोजन की चुनौतियों से संघर्ष कर रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से वर्ष 2021 तक 1.4 करोड़ से अधिक की आबादी वाला यह शहर भारतीय संदर्भ में शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कोलकाता में प्रभावी शहरी नियोजन के लिए बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता, पर्यावरणीय स्थिरता, परिवहन प्रबंधन में कमी और आवास से लेकर कई मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है।

कोलकाता की जनसंख्या वृद्धि के मामले ने इसके बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव डाला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, कोलकाता में जनसंख्या घनत्व 24,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक था। जो इसे दुनिया के सबसे घने शहरी क्षेत्रों में से एक बनाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान एक नियोजित शहर होने के बावजूद, बुनियादी ढांचे को आधुनिक मांगों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। यहां पर झुग्गी-झोपड़ियों की आबादी में वृद्धि के संदर्भ में अनुमान है कि 15 लाख निवासी अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं जो उपलब्ध आवास और मांग के बीच अंतर को रेखांकित करता है।

शहरी गरीबों के पास अक्सर पीने योग्य साफ पानी, स्वच्छता और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच नहीं होती है। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 30% घरों में पाइप से पानी की पहुंच नहीं है। वे साझा सामुदायिक नल या भूजल स्रोतों पर निर्भर हैं। जैसा कि हाल के वर्षों में देखा गया है कि अत्यधिक बोझ वाले सीवेज और जल निकासी प्रणालियां मानसून के दौरान बाढ़ को बढ़ा देती हैं और शहर के बड़े हिस्से में कई दिनों तक पानी भरा रहता है।

कोलकाता की शहरी योजना के लिए परिवहन एक महत्वपूर्ण बाधा है। जबकि शहर को भारत की पहली मेट्रो प्रणाली होने पर गर्व है, जिसका उद्घाटन 1984 में हुआ था परंतु समग्र सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। शहर की बसों, टैक्सियों और ऑटो-रिक्शा पर निर्भरता के परिणामस्वरूप सड़कों पर भीड़ से यातायात और वाहन प्रदूषण होता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के वर्ष 2021 के एक अध्ययन में कोलकाता को भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में स्थान दिया गया था। जिसका मुख्य कारण सड़कों पर चलने वाले वाहनों से होने वाला उत्सर्जन है। कोलकाता ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट है कि दैनिक वाहन पंजीकरण में 10% की वृद्धि हो रही है, जिससे पहले से ही भीड़भाड़ वाली सड़कों पर दबाव बढ़ रहा है।

कोलकाता की मेट्रो विस्तार परियोजनाएं और ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर भविष्य के लिए आशा प्रदान करते हैं लेकिन फंडिंग और भूमि अधिग्रहण चुनौतियों के कारण

इसमें देरी हो रही है। कुछ इलाकों में मेट्रो सेवा का विस्तार हुआ है जैसे, सियालदह से नई टाउन सेक्टर 5 तक, रूबी से न्यू गड़िया, दक्षिणेश्वर से न्यू गड़िया और हावड़ा मैदान से एस्प्लानेड तक, परंतु इसको पूरा होने में समय लगेगा। टिकाऊ शहरी गतिशीलता समाधान के लिए जैसे साइकिल चलाना और पैदल यात्री-अनुकूल क्षेत्रों को बढ़ावा देना इत्यादि पर कार्य अभी तक शहर नियोजन में जोर नहीं पकड़ पाया है।

कोलकाता में रियल एस्टेट बाजार भी एक द्वंद्व का सामना कर रहा है। न्यू टाउन और साल्ट लेक जैसे क्षेत्रों में लक्जरी अपार्टमेंट प्रचुर मात्रा में हैं लेकिन किफायती आवास बहुमत के लिए मायावी बना हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) जैसी भारत सरकारी पहल का उद्देश्य आवास की कमी को दूर करना है लेकिन इसका कार्यान्वयन यहां पर धीमा रहा है। करीब 30% से अधिक आबादी झुग्गी-झोपड़ियों और बस्तियों में रहने के कारण यह शहर अनियोजित शहरी फैलाव से जूझ रहा है। राजारहाट जैसे उप-शहरी क्षेत्रों में विस्तार के कारण कृषि भूमि और आर्द्रभूमि का तेजी से नुकसान हुआ है। पूर्वी कोलकाता के जल श्रोतों जैसे, एक यूनेस्को-मान्यता प्राप्त रामसर साइट है जो कि शहर के अपशिष्ट जल के प्रबंधन में बड़ी भूमिका निभाता है। पर वो भी पारिस्थितिक महत्व के बावजूद लगातार अतिक्रमण से खतरे में है। इन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को शहरी विकास योजनाओं में एकीकृत किया जाना चाहिए। वैसे देखा जाय तो कोलकाता जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा का पैटर्न, अम्फान (2020) और डाना (2 0 2 4) जैसे चक्रवातों की बढ़ी हुई आवृत्ति शहरी नियोजन में लचीलेपन की आवश्यकता को उजागर करती है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) ने कोलकाता को समुद्र के स्तर में वृद्धि और तूफान के कारण सबसे अधिक जोखिम वाले शहरों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया है।

शहर में हरित स्थान भी तेजी से सिमट रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर की एक रिपोर्ट में पाया गया कि वर्ष 1980 और वर्ष 2010 के बीच, कोलकाता का हरित आवरण 44% कम हो गया है। जिसका मुख्य कारण अनियमित निर्माण कार्य बताया गया था। शहरी नियोजन को पार्कों, हरित पट्टियों और टिकाऊ वास्तुकला के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए जो ऊर्जा की खपत को कम करे। केएमसी प्रतिबंध के तहत शहर ने प्लास्टिक बैग के उपयोग में 90% की कमी हासिल की और ठोस अपशिष्ट पृथक्करण के लिए पहल शुरू की है। हालांकि, समग्र और एकीकृत शहरी विकास हासिल करने के लिए बहुत काम बाकी है। कोलकाता के लिए शहरी नियोजन में एक महत्वपूर्ण चुनौती कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए), केएमसी और राज्य सरकार एजेंसियों सहित कई शासी निकायों की ओवरलैपिंग जिम्मेदारियों में निहित है। खराब समन्वय के कारण परियोजना निष्पादन में देरी, संसाधनों का कुप्रबंधन और नीतिगत पंगुता होती है। इसके अलावा, धन की कमी अक्सर शहरी नवीनीकरण की महत्वाकांक्षी योजनाओं को बाधित करती है। कोलकाता ने अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कुछ क्षेत्रों में प्रगति की है। कोलकाता को टिकाऊ शहरीकरण के एक मॉडल के रूप में उभरने के लिए, इसकी शहरी योजना को बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। सबसे पहले सार्वजनिक परिवहन में निवेश किया जाना चाहिए। जैसे, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करें, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम विकसित करें, सड़कों पर फ्लाईओवर बनाएं और भीड़भाड़ और प्रदूषण को कम करने के लिए साइक्लिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दें। दूसरा, समावेशी आवास नीतियां बनाई जानी चाहिए जिससे स्लम पुनर्वास योजनाओं के बेहतर एकीकरण के साथ किफायती आवास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाना जरुरी है। आर्द्रभूमियों, वेटलैंड्स और हरित स्थानों को शहर के बुनियादी ढांचे में एकीकृत करते हुए उनके लिए कानूनी सुरक्षा को मजबूत करना पड़ेगा और चौथा है, कोलकाता को स्मार्ट सिटी बनाने की पहल करना। इसके लिए अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा-कुशल इमारतों और वास्तविक समय यातायात निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं। आखिरी है, जलवायु परिवर्तन पर प्रबंधन जिससे समुद्र के बढ़ते स्तर से होने वाले जोखिमों को कम करने और आपदा तैयारियों में सुधार के लिए नीतियां विकसित करना।

कोलकाता में शहरी नियोजन विरासत, जनसंख्या वृद्धि और आधुनिकीकरण को संतुलित करने में भारतीय शहरों के सामने आने वाली व्यापक चुनौतियों को दर्शाता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक दूरदर्शी नेतृत्व, सभी की सामुदायिक सहभागिता और उन्नत किस्म की नवोन्मेषी नीतियों की आवश्यकता है जो शहर की स्थिरता को प्राथमिकता दें। भारत के सबसे प्रतिष्ठित शहरों में से एक के रूप में कोलकाता जैसे तेजी से बढ़ते शहरों में शहरी नियोजन की असंख्य चुनौतियों को स्वीकार करके दूरदर्शिता और समावेशिता के साथ शहरीकरण से निपटने में दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने का अवसर है।

सुओमोटो के तहत सड़क सीमा से हटाए अतिक्रमण

उप महानिरीक्षक पुलिस जविप्रा कैलाश चन्द विश्नोई ने नवीन अवैध कॉलोनियों पर कसा कानूनी शिकंजा, चलाया पीला पंजा

जयपुर विकास प्राधिकरण ने 27 बीघा भूमि पर छः अवैध कॉलोनियों को किया पूर्णतः ध्वस्त

चमकता राजस्थान

जयपुर! (खलील कुरैशी) 14 दिसम्बर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-11 में निजी खातेदारी की करीब 11 बीघा कृषि भूमि पर 02 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त एवं जोन-12 में निजी खातेदारी की करीब 16 बीघा कृषि भूमि पर 04 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। साथ ही सुओमोटों के तहत सुषांत सिटी में रोड़सीमाकोकब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया जोन-11 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम पवालिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में करीब 07 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीएकीबिनास्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही जोन-11 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। जोन-11 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम पवालिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में ही एच.पी. गैस गोदाम के पास करीब 04 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीएकीबिनास्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल, सडकें,बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-11 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।जेडीए द्वारा जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम भंभोरी, जिला जयपुर में करीब 07 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ''करणी विहार'' के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल, सडकें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम भंभोरी, जिला जयपुर में ही करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ''सरिता विहार'' के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल, सडकें, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

इसी प्रकार जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम सबरामपुरा, जिला जयपुर में करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ''कृष्णा विहार'' के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल, सडकें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम सबरामपुरा जिला जयपुर में ही करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीएकीबिनास्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ''प्रेम नगर'' के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल, सडकें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया जेडीए द्वारा जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सुशांत सिटी में रोड़ सीमा पर करीब 08 स्थानों पर कब्जा-अतिक्रमण कर अवैध रूप से अत्यधिक लम्बाई में चबूतरे, लोहे के एंगल, झाालियां इत्यादि लगाकर किये गये अतिक्रमणों के संबंध में अतिक्रमणकर्ताओं को सुओमोटो के तहत नोटिस जारी कर मुनादी की गई एवं अतिक्रमण हटाने हेतु पाबंद किया गया परन्तु अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांकः 14.12.2024 को जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, तृतीय प्रवर्तन अधिकारी जोन-11, 12 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई। प्रवर्तन प्रकोष्ठ जविप्रा द्वारा माह अक्टूबर वर्ष 2024 से तक कुल 85 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया।

संक्षिप्त समाचार

जिला प्रशासन के प्रयास लाए रंग...एक महीने में 211 राहें हुई आसान

- जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश सभी तहसीलों में जारी है रास्ता खोलो अभियान
- बरसों पुराने रास्ते खुलवाए जाने पर ग्रामीणों ने जताया जिला प्रशासन का आभार

चमकता राजस्थान। जयपुर! (खलील कुरैशी) 14 दिसंबर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर शुरू हुआ रास्ता खोलो अभियान ग्रामीणों के लिए राहत का दूसरा नाम बन गया है। अभियान के तहत जिला प्रशासन ने समझाइश एवं सहमति से गांवों, खेतों और ढाणियों के बरसों से बंद पड़े 211 रास्ते खुलवाने में कामयाबी हासिल की है।अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अभियान की नोडल अधिकारी सुमन पंवार ने बताया कि अभियान के तहत जोबनेर तहसील में सर्वाधिक 17 रास्ते तो वहीं, चौमूं तहसील में 16 रास्ते खुलवाए गए। आमेर, आंधी, शाहपुरा, किशनगढ़-रेनवाल, फुलेरा तहसील में 15-15 रास्ते तो वहीं, सांगानेर, माधोराजपुरा तहसील में 14-14 रास्ते खुलवाए गए। उन्होंने बताया कि चाकसू तहसील में 11 रास्ते, जमवारामगढ़ तहसील में 10 रास्ते, बस्सी, रामपुरा-डाबड़ी, जालसू एवं कोटखावदा तहसील में 9-9 रास्ते, कालवाड़ एवं तुंगा तहसील में 7-7 रास्ते तो वहीं, जयपुर तहसील में 4 रास्ते खुलवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को रास्ता खोलो अभियान के तहत बंद रास्ते खुलवाए जाने के पश्चात खोले गए रास्तों पर ग्रेवेल, सी.सी. रोड़ बनवाये जाने की कार्यवाही भी जल्द से जल्द अमल में लाने के निर्देश दिये हैं, इन निर्देशों की अनुपालना में अधिकांश स्थानों पर ग्रेवल रोड बनाने की कार्यवाही भी आरंभ की जा चुकी है। वहीं, जिन रास्तों के वाद न्यायालय में विचाराधीन है परिवादियों द्वारा संबंधित न्यायालय से ही अनुतोष प्राप्त किया जाएगा।ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में परिवाद प्राप्त होते हैं। रास्तों को लेकर न्यायालय में भी वाद दायर किए जाते रहते हैं। ऐसे प्रकरणों में निरन्तर बढ़ोतरी होने से आमजन को न्यायालय के चक्कर लगाने एवं जन-धन की हानि होने के साथ-साथ क्षेत्र की कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसलिए प्रशासन ने रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के लिए 'रास्ता खोलो अभियान' चलाने का निर्णय लिया गया।

रविवार को होगा अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ

- खेल एवं युवा मामलात मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करेंगे उद्घाटन
- देशभर की 33 टीमें प्रतियोगिता में दिखाएंगी दमखम

चमकता राजस्थान

जयपुर,! (खलील कुरैशी) 14 दिसंबर। अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस (पुरूष/महिला) खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार, 15 दिसंबर 2024 को प्रातः 11:30 बजे होगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में रविवार को आयोजित होने वाली प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल एवं युवा मामलात मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करेंगे।21 दिसंबर तक आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न प्रदेशों से रीजनल स्पोर्ट्स बॉडी, राज्य सचिवालय, केन्द्र शासित प्रदेशों की कुल 33 टीम भाग लेंगी। शनिवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित मैनेजर कमेटी की बैठक में मुकाबलों के ड्रा निकाले गए।

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने की मुलाकात

चमकता राजस्थान। जयपुर! (खलील कुरैशी) 14 दिसंबर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से राजभवन में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की। राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

सेक्टर कॉमर्शियल संपत्ति चिन्हित कर रखी जायेगी नीलामी में,शीघ्र लांच की जायेंगी योजनाएं

जयपुर विकास आयुक्त आनन्दी ने ली समस्त प्रकोष्ठों की समीक्षा बैठक, दिये विभिन्न आवश्यक दिशा-निर्देश

चमकता राजस्थान

- जयपुर शहर के विकास को गति देने हेतु राजस्व अर्जन पर विशेष फोकस करने के दिए निर्देश
- सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाते ही करवाई जायेगी प्लानिंग,लीजडीड बकायादारों को जारी किये जायेंगे नोटिस
- कोर्ट कैसेज की पेंडेंसी को कम करने एवं अवैध रूप से संचालित विवाह स्थलों को नोटिस द्वारा की जायेगी नियमानुसार कार्यवाही
- भूमि के बदले भूमि के संबंधित प्रकरणों का निस्तारण सामुहिक रूप से करने के दिए निर्देश

जयपुर!(खलील कुरैशी) 14 दिसम्बर। स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा महोदय के मार्गदर्शन में जयपुर विकास आयुक्त आनन्दी की अध्यक्षता में शनिवार को जेडीए के मंथन सभागार में जविप्रा के समस्त प्रकोष्ठों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में डीटीएस, सम्पर्क पोर्टल, लोकायुक्त प्रकरणों, मानव अधिकार आयोग प्रकरण, विधानसभा प्रश्नों के लम्बित प्रकरणो को गुणात्मक रूप से तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिये। नागरिक सेवा केंद्र में समस्त प्रकार के दर्ज ऑनलाईन प्रकरणों की पेडेंसी शून्य करने एवं बीपीसी एलपी, बीपी, बिल्डिग प्लान एवं 90ए के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिये। लाईट्स प्रकरणों (कोर्ट कैसेज) का निस्तारण त्वरित गति से करने एवं इससे संबंधित प्रकरणों की निरंतर मॉनिटरिंग कर पेन्डेन्सी शून्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कोर्ट में लंबित प्रकरणों की प्रभावी एवं पुख्ता पैरवी नहीं करने वाले अधिवक्ताओं को बदलने के निर्देश दिये, जिससे जेडीए के पक्ष में निर्णय पारित हो सके। उन्होंने समस्त जोन उपायुक्तों को कोर्ट में लंबित प्रकरणों का जवाब प्रभावी एवं गुणात्मक रूप से तैयार कर पेश करने के सख्त निर्देश दिये। बैठक में प्रवर्तन शाखा द्वारा जिन सरकारी भूमियों से अवैध कब्जे-अतिक्रमण हटवाये गये, की जानकारी दी गई। जेडीसी ने जोन उपायुक्तों को अतिक्रमण मुक्त करवाई गई लगभग 250 बीघा सरकारी भूमि की फैंसिंग करवाने एवं जेडीए संपत्ति के बोर्ड लगवाते हुए तत्काल रूप से प्लानिंग करने के निर्देश दिये। जिससे अतिक्रमी द्वारा पुनः अतिक्रमण नहीं किया जा सके।

धारा 177 की कार्यवाहियों हेतु लंबित पत्रावलियों का निस्तारण करने हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिये। जेडीए क्षेत्राधिकार में अवैध रूप से संचालित विवाह स्थलों को नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जेडीसी ने जेडीए द्वारा सृजित की जाने वाली आवासीय/अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने योजनाओं को शीघ्र लांच करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि जेडीए द्वारा विभिन्न प्रकार - एग्रो वेयर हाउस, वेयर हाउस, फार्म हाउस, व्यावसायिक, आवासीय एवं अन्य योजनाएं लांच करने हेतु प्लानिंग की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने समस्त जोन उपायुक्तों को अपने-अपने जोन्स में नवीन योजनाएं सृजित करने हेतु भूमि चिन्हिकरण करने के निर्देश दिये। बैठक में निर्देश दिये गये कि नवीन योजनाओं के अनुमोदन के प्रस्ताव आगामी पीडब्ल्यूसी की बैठक में रखें। इसके साथ ही जिन योजनाओं का अनुमोदन किया जा चुका है, उनमें विकास कार्यो हेतु स्वीकृतियॉ ली जाकर मूलभूत विकास कार्य करवाने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि जोन-11 में ग्राम सिराणी एवं ग्राम चतरपुरा में दो योजना, जोन-14 में ग्राम काठावाला एवं ग्राम झुझारपुरा में दो योजना हेतु भूमि की प्लानिंग की जा रही है। जेडीए द्वारा जोन-12 में नारी का बास, रोजदा, जयरामपुरा फार्म हाउस, जोन-10 में गोविंदपुरा रोपाडा व खोरी रोपाडा, जोन-11 में चिरोटा में नवीन योजनाएं शीघ्र लाई जायेंगी। राजस्व अर्जन हेतु जेडीए योजनाओं में उपलब्ध भूखण्डों को नीलामी में प्राथमिकता से रखने के निर्देश दिये। जेडीसी ने समस्त जोन उपायुक्तों एवं अधिशाषी अभियंताओं को जेडीए के जोन-9 से 14 तक सेक्टर कॉमर्शियल/अन्य प्रकार की संपत्तियों को चिन्हित कर नीलामी में प्रमुखता से रखने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि राजस्व अर्जन हेतु विभिन्न जोनों में बडे भूखण्डों की लीज राशि बकाया है। जोन उपायुक्तों को ऐसे व्यावसायिक, संस्थागत एवं ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों की सूची तैयार कर संबंधित को नोटिस जारी कर नियमानुसार लीज राशि वसूलने के निर्देश दिये गये।

जेडीसी ने उपायुक्तों से आगामी माह में आयोजित किये जाने वाले नियमन शिविरों की प्रगति की जानकारी ली एवं नियमित रूप से नियमन शिविर आयोजित करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही प्रशासन शहरों के संग अभियान में दी जा रही शिथिलताओं के बिना जिन योजनाओं से संबंधित संस्था/अधिकृत व्यक्ति नियमन शिविर आयोजित करवाने के इच्छुक है, उनसे संपर्क कर नियमन शिविर आयोजित करें। भूमि के बदले भूमि के संबंधित प्रकरणों का निस्तारण योजनावार एवं ग्रामवार सामुहिक रूप से करने के निर्देश दिये। जिससे कम समय में गुणात्मक रूप से प्रकरणों का निस्तारण संभव हो सकेगा। बैठक में 9 मुख्य सडकों/स्थानों पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये, जिससे निर्बाध एवं सुरक्षित यातायात आमजन को उपलब्ध हो सकेगा। इस क्रम में जैसे-जैसे अतिक्रमण हटवाये जा रहे वहॉ सडकों का निर्माण करवाया जाता रहे। इस हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियॉ दी जा चुकी है। इसके साथ ही जेडीए के जोन कार्यालयों द्वारा निरंतर ई-फाईल हेतु स्केनिंग का कार्य करवाया जा रहा है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। इस हेतु एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म तैयार करने के निर्देश भी दिये गये। जेडीसी ने जेडीए द्वारा जयपुर में विकास कार्यो को गति देने हेतु राजस्व अर्जन पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिये। उन्होंने जोन उपायुक्तों को भूखण्डों की नीलामी में रखने का प्रस्ताव नीलामी शाखा में भेजने के निर्देश दिये। इसके साथ ही जोन में नीलामी में रखी जाने वाली संपत्तियों को चिन्हित करने के निर्देश भी दिये। नीलामी शाखा को आगामी माह में लगभग 200 परिसंपत्तियों को ई-ऑक्शन में रखने के निर्देश दिये।

जयपुर ज्वैलरी शो 2024 अपने 22वें वर्ष में 20 दिसंबर से 23 दिसंबर, रहेगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी

चमकता राजस्थान

जयपुर! (खलील कुरैशी) 14 दिसंबर। देश का नंबर वन बी2बी एवं बी2सी शो - 'जयपुर ज्वलैरी शो' का आयोजन 'रूबीज... रेयर, रॉयल और रेवर्ड' थीम के साथ जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में 20 से 23 दिसंबर 2024 को होने जा रहा है। जेजेएस दिसंबर शो के रूप में विश्वभर में अपनी खास पहचान बना चुका है, जिसमें शीर्ष जवाहरात कारोबारी अपनी नयी डिजायन और बेहतरीन कारीगरी को प्रदर्शित करते हैं और देश-विदेश के सालाना कलैण्डर में जेजेएस को स्थान दिया जाता है। जेजेएस चेयरमैन, विमल चंद सुराणा ने कहा कि जेजेएस अपनी पूरी भव्यता के साथ दिसंबर में आयोजित किया जा रहा है। शो को सफल बनाने के लिए जेजेएस टीम पूरे जोश और मेहनत के साथ कार्य में जुटी हुई है। 'द दिसंबर शो' के लिए इस वर्ष एग्जीबिटर्स में उत्सुकता देखने को मिल रही है।

● जेजेएस पृष्ठभूमि

जेजेएस चेयरमैन, विमल चंद सुराणा ने कहा कि 2003 में एंटरटेनमेंट पैराडाइज (ईपी) में 67 स्टालों के साथ हुई शुरूआत में काफी उत्साहजनक प्रतिक्रिया, संवाद और उत्सुकता देखने को मिली थी। वहीं 2004 में लंबी छलांग देखेने को मिली जहां जेजेएस में 189 बूथ लगाए गए। उसके बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2005 में, वेन्यू को राजमहल पैलेस में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें 276 स्टॉल थे। इस जगह ने प्रदर्शकों, अन्य प्रतिभागियों और आगंतुकों को अधिक स्पेस और सुविधाएं प्रदान की। 2023 में 1100 बूथ्स थे। विक्रेताओं और खरीदारों के लिए उत्तम अनुभव बनाने के लिए, जेजेएस अपने 22वें वर्ष में 1200 से ज्यादा बूथ्स की मेजबानी करने जा रहा है। यह ब्रांड जेजेएस और 8 वर्ष पहले वेन्यू परिवर्तित करके जेईसीसी में आयोजन करने के कारण यह संभव हो पाया है। इसके कारण से बूथों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।

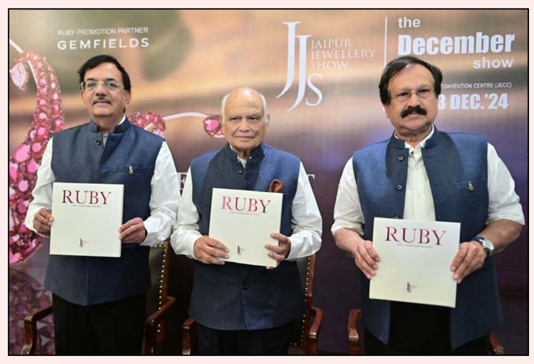

● मुख्य अतिथि एवं समारोह का उद्घाटन

जेजेएस मानद सचिव राजीव जैन के अनुसार गत पिछले वर्षों से जेजेएस के मुख्य अतिथि रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के विशिष्ठ शख्सियत होते हैं। इस वर्ष भी जयपुर कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार 20 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे जेजेएस का विधिवत उद्घाटन समारोह आयोजित होगा।

● 1200 से अधिक बूथ्स होंगे

जेजेएस के मानद सचिव, राजीव जैन ने बताया कि वर्ष 2003 में रश्मिकांत दुर्लभजी द्वारा शहर के एंटरटेनमेंट पैराडाइज में मात्र 67 स्टॉल्स के साथ जेजेएस की शुरूआत की गई थी। जेजेएस वर्ष 2024 में जयपुर कन्वेंशन सेंटर में 1200 से ज्यादा बूथ्स होंगे। इनमें से 329 बूथ्स जेमस्टोन्स की होंगी, 723 बूथ्स पर ज्वैलरी प्रदर्शित की जायेंगी जबकि 13 पर कॉस्ट्यूम एवं सिल्वर आर्टिकल्स प्रदर्शित होंगे। इसके अतिरिक्त, 58 बूथ्स पर अलाईड मशीनरी के होंगे।राजीव जैन ने कहा कि जेजेएस में इस वर्ष भी ज्वैलरी सैक्शन में लगभग 66 प्रतिशत डिजाइनर बूथ्स हैं, जो जेजेएस को न केवल खूबसूरत बनाएंगे...बल्कि विजिटर्स को नयेपन का एहसास होगा।

● पुराने और नए एग्जीबिटर्स की भागीदारी

राजीव जैन के अनुसार जेजेएस के गत संस्करण की भांति एरिया में समानता होगी। जेजेएस में ना केवल पुराने एग्जीबिटर्स लगातार जुड़े हुए हैं, बल्कि नए एग्जीबिटर्स भी जयपुर के इस ब्रान्ड में भाग लेने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। जेजेएस-2024 में नए एक्जीबीटर्स के साथ- साथ ही कई राष्ट्रीय ब्रांड भी हिस्सा लेंगे। इस बार जेजेएस में 8,000 से अधिक ट्रेड विजिटर्स और लगभग 50,000 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विजिटर्स शामिल होंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बूथ्स में 10% की वृद्धि हुई है।

● राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी:

जेजेएस-2024 में तीन अंतरराष्ट्रीय एग्जीबिटर्स भी आएंगे। जिसमें बैंकॉक से एक बूथ और हॉगकॉग से 1 बूथ होगा। इसके अतिरिक्त, जयपुर सहित मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद और अहमदाबाद से भी एग्जिबिटर्स शामिल होंगे।

● पिंक क्लब

जेजेएस मानद सचिव, राजीव जैन से बताया कि पिछले वर्ष, जेजेएस 2022 में पिंक सिटी के नाम पर नया एक्सक्लूसिव बी2बी पवेलियन 'पिंक क्लब' जोड़ा गया था, जो तब से जेजेएस में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। इस वर्ष, जेजेएस 2024 में भी पिंक क्लब नए स्थान पर होगा और यह ज्यादा स्पेस के साथ हॉल 2 का हिस्सा होगा। पिंक क्लब में 98 प्री-फैब्रिकेटेड बूथ्स होंगे और केवल बी2बी ग्राहक ही इस पवेलियन में जा सकते हैं। इस पवेलियन में एक विशेष लाउंज और कॉम्पलीमेंट्री चाय/कॉफी और मुफ्त वाई-फाई भी होगा।

● नेटवर्किंग डिनर

राजीव जैन ने यह भी बताया कि जेजेएस 2024 की एक और रोमांचक विशेषता 21 दिसंबर को शानदार नेटवर्किंग ईवनिंग का आयोजन होगी। यह शाम प्रदर्शकों को शीर्ष रीटेलर्स और जेजेएस के खरीदारों के साथ डिनर और लाइव बैंड प्रस्तुति का आनंद लेते हुए बातचीत करने का अवसर और मंच प्रदान करती है।

● द दिसंबर शो

जेजेएस प्रवक्ता, अजय काला के अनुसार 'दिसम्बर शो' के रूप में लोकप्रिय जेजेएस में लगभग 50,000 देशी एवं विदेशी विजिटर्स के साथ यह देश का एक महत्वपूर्ण आयोजन बन चुका है। इस शो की खासियत व्यापारी व ग्राहक को एक साथ जयपुर की दक्षता व हुनर का प्रदर्शन है। देश में किसी ज्वैलरी शो में आम ग्राहक को इस भव्यता व व्यवस्थित ढंग से माल देखने को नहीं मिलता। इस दौरान आगंतुकों को रत्न और आभूषण उद्योग द्वारा पेश की गई नवीनतम और बेहतरीन ज्वैलरी और जेम्स को देखने का अवसर मिलता है। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों और आगंतुकों के वार्षिक कैलेंडर में इस शो को शामिल किया गया है। अनेक टूर ऑपरेटरर्स ने इस प्रतिष्ठित शो को अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल किया है, जिससे विदेशी और भारतीय पर्यटकों को जेजेएस में विजिट करने के विशेष प्लान को सरल बनाते हैं।

मीडिया ब्लिट्ज अजय काला ने कहा कि जयपुर को जेम एंड ज्वैलरी में एक ब्रांड बनाने के लिए - पिछले वर्षों की तरह, जेजेएस 2024 कुछ संगठित और सुनियोजित प्रचार-प्रसार करेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चुनिंदा मेल प्रचार अभियान को अत्यधिक प्रभावी बना देगा। इसके अतिरिक्त, हाईवे होर्डिंग्स और एफएम रेडियो का विवेकपूर्ण उपयोग भी होगा। न केवल जयपुर में बल्कि अन्य शहरों में भी व्यापक कवरेज के साथ इस वर्ष आउटडोर प्रचार भी किया जाएगा।उन्होंने आगे बताया कि प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों का स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों; राष्ट्रीय उपभोक्ता प्रकाशन और व्यापार प्रकाशन में प्रचार होगा। रेडियो एफएम जो एक ऐसा प्रचार एजेंट बन गया है, इसमें रेडियो सिटी, एफएम तड़का, माई एफएम, रेड एफएम और रेडियो मिर्ची में प्रचार किया जाएगा। जेजेएस कैलेंडर, नोट बुक, स्लिप पैड आदि के रूप में सीधा प्रचार किया जाएगा।

● जेजेएस रूबी प्रमोशन ग्रुप

जेजेएस वाईस चेयरमैन, दिनेश खटोरिया ने बताया कि जयपुर ज्वैलरी शो अपने 22वें वर्ष में थीम 'रूबीज... रेयर, रॉयल और रेवर्ड' लेकर आया है। पिछले दो वर्षों में एमरल्ड पर फोकस करने के बाद, इस वर्ष के शो में रूबी आभूषणों को विशेष महत्व दिया जाएगा। रूबी को उसकी दुर्लभता और शाही प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है, और यह कीमती रत्न भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय आभूषण डिज़ाइन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रूबी आभूषणों की विविधता, उनकी गुणवत्ता, और डिज़ाइनों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ज्वैलरी डिजाइनर्स और निर्माता अपनी रचनाओं में नई तकनीकों और डिज़ाइनों को पेश करेंगे जो इस कीमती रत्न को नये आयामों में प्रस्तुत करेंगे।इस विशेष रत्न को प्रमोट करने के लिए रूबी प्रमोशन ग्रुप का शुभारंभ भी किया गया है, जिसका उद्देश्य रूबी से संबंधित समस्याओं जैसे कटिंग, पॉलिशिंग, ट्रीटमेंट, और सर्टिफिकेशन पर विचार करना है। यह प्रमोशनल ग्रुप रूबी के उद्योग में मानकों और गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेगा। मिस इंडिया वर्ल्ड 2023, नंदिनी गुप्ता, इस वर्ष के शो की ब्रांड एंबेसडर है।

● लंच एवं टी

जेजेएस वाईस चेयरमैन, श्री दिनेश खटोरिया ने बताया कि विजिटर्स एक बार फिर कॉम्पलीमेंट्री लंच में स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेंगे, जिसे वर्षों से काफी सराहा गया है। इस वर्ष यह बदलाव किया गया है, कि हॉल 1 और हॉल 2 दोनों में लंच एरिया अलग-अलग होगा। 4 कैंटीन के माध्यम से भुगतान के आधार पर चाय, कॉफी आदि की भी व्यवस्था की गई है।

'जेजेएस-आईजे डिजाइन अवॉर्ड्स कमल कोठारी, कोषाध्यक्ष के अनुसार जीआईए द्वारा संचालित जेजेएस-आईजे डिजाइन अवाड्र्स इस वर्ष फिर से आयोजित किए जाएंगे। इस प्रतिष्ठित आयोजन की प्रतीक्षा की जा रही है। विजेताओं का चयन ग्रैंड जूरी मीट में किया गया था। अब अपने 14वें वर्ष में, 'जेजेएस-आईजे डिजाइन अवाड्र्स' ने भारत और दुनिया के आभूषणों के पारखी लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया है। साल दर साल, इस पुरस्कार ने केवल डिजाइन और रचनात्मकता में देश के सर्वश्रेष्ठ को अधिक बेहतर बनाया है और सम्मानित किया है। इस साल ज्वैलरी डिजाइनिंग में कई इंटरनेशनल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इस देश में डिजाइन प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन यह देखना हमेशा दिलचस्प होता है कि विशाल मात्रा में कैसे प्रतिभाएं पहनने योग्य, सुंदर पीस का निर्माण करती हैं। कमल कोठारी के अनुसार इस साल आईजे अवॉर्ड्स में 1000 से ज्यादा डिजाइनों शामिल हुईं। इनमें से, 133 से अधिक डिजाइनों का मूल्यांकन प्रख्यात जूरी द्वारा किया गया। 20 दिसंबर की शाम को अटलांटिस बैंक्वेट्स में एक भव्य समारोह में यह पुरस्कार जेजेएस की ब्रांड एम्बेसेडर मिस इंडिया वर्ल्ड 2023, नंदिनी गुप्ता द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

● 1000 टॉप रिटेलर्स

विजय चौरड़िया के अनुसार इस वर्ष भारत के लगभग 1000 टॉप ज्वैलरी रिटेलर्स ने जेजेएस में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। जेजेएस के निमंत्रण पर ये रिटेलर्स प्रत्येक वर्ष शो विजिट करते हैं और शो के दौरान बी2बी बायर्स के रूप में अपने प्रोडक्टस की नियमित आपूर्ति के लिये सम्पर्क बनाते हैं। ताकि बायर्स का भी निरन्तर रूप से ज्वेलरी मैन्यूफैक्चरर्स से सम्पर्क हो सके।

● जीजेसी के 50 से अधिक सदस्य भाग लेंगे

विजय चौरड़िया के अनुसार ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वैलरी डॉमेस्टिक काउंसिल (जीजेसी) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शो के लिए जेजेएस द्वारा आमंत्रित किया गया। जीजेसी पूरे भारत में रत्न और आभूषण के व्यापार का विकास और प्रचार के लिए नेशनल ट्रेड फेडरेशन है। देश के 50 से अधिक शीर्ष ज्वैलरी रीटेलर्स इस शानदार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उन्हें शो में बड़ी संख्या में बूथों से आइटम्स चुनने का अवसर भी मिलेगा। उनकी उपस्थिति प्रदर्शकों को जैम एंड ज्वैलेरी क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञों से चर्चा करने का अवसर भी प्रदान करेगी।जोनल कन्वीनर्स मीटिंग की बैठक में 50 से अधिक जीजेसी- ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल मेम्बर्स भाग लेंगे।

● आईबीजेए के 30 से अधिक सदस्य

विजय चौरड़िया ने आगे यह भी बताया कि जेजेएस में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी आईबीजेए के सदस्यों को आमंत्रित और होस्ट किया गया है। 20 दिसंबर को आईबीजेए के सदस्यों के लिए मीटिंग आयोजित होगी।

● प्रतिष्ठित पार्टनर्स

अशोक सिंघी ने बताया कि जीआईए, डीटीसी, जीजेईपीसी, डब्लूएफडीबी, सीआईबीजेओ, जीजेसी, एनजीजेसीआई, आईबीजेए, आईसीए, रियो-टिंटो, जेम्सफील्ड, जी एंड जे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडीज, एसोसिएशंस, माइनर्स, आईजीआई और एसजीएल सभी जेजेएस के प्रतिष्ठित पार्टनर्स रहे हैं। उनके कौशल और पेशेवर कामकाज ने इस मेगा इवेंट में मूल्यवर्धन किया है।

● सुरक्षा एवं इन्श्योरेंस

अशोक सिंघी के अनुसार पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी आयोजकों ने सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत कैमरों के साथ-साथ जेजेएस के स्तर पर भी व्यवस्था की है। इस वर्ष सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए कॉमन एरिया में लगभग 500 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। इस वर्ष भी दर्शकों के लिए बार कोडेड एंट्री सिस्टम होगा।

● बिजनेस ऑवर्स

उमेश डंगायच ने जानकारी दी की यह शो बिजनेस विजिटर्स के लिए सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा। आम विजिटर्स के लिए शो का समय दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। आखिरी दिन यानी सोमवार, 23 दिसंबर को शो का समय शाम 6.30 बजे तक रहेगा। (एग्जीबिशन हॉल में प्रवेश समापन समय से 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा)

● नं. 1 बी2बी और बी2सी शो

जगदीश ताम्बी के अनुसार जेम्स एंड ज्वैलरी शो पूरी दुनिया में आयोजित किए जाते हैं। हालाँकि ये भारत में एक्सक्लूसिव इ2इ इंटरनेशनल शो या कंज्यूमर शो होते हैं। इसके अतिरिक्त, जेजेएस एक अनूठा शो है जिसने बी2बी और बी2सी दोनों शो पर ध्यान केंद्रित किया है। ज्वैलर्स और उपभोक्ताओं को यह दुर्लभ प्लेटफॉर्म 360 डिग्री फीडबैक के लिए उपयुक्त लगता है। जबकि ज्वैलर्स रंगीन रत्न और हीरे दोनों की एक विस्तृत विविधता के सामान्य प्रदर्शन में आते हैं - मेटल्स, बीड्स और कार्विंग समान रूप से लोकप्रिय हैं।वहीं, बी2सी - उपभोक्ताओं को 1200 से अधिक बूथों पर इतने आसान प्रारूप में प्रोडक्ट प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा। यहां वे आसानी से कई विक्रेताओं से चुन सकते हैं और खरीद सकते हैं। वे अपने रीटेलर्स और दोस्तों के साथ पीस का मिलान कर उसे अंतिम रूप दे सकते हैं - जो उनके लिए एक अद्भुत अनुभव बनाता है।

● ज्वैलरी में नए ट्रेंड्स पर फोकस

मेहुल दुर्लभजी ने बताया कि जयपुर ज्वैलरी शो की एक विशेष खासियत नवीनतम डिजाइनों, ज्वैलरी की नई सेटिंग्स पर ध्यान केंद्रित करना है। लोगों को पारंपरिक भारी सोने के गहनों से लेकर हल्के वजन के आभूषणों के नये फैशन देखने को मिलते हैं। जो लोग फैशन एक्सेसरीज और स्टोन जड़ित ज्वैलरी की तलाश में हैं, वे निराश नहीं होंगे। पीले और सफेद सोने के गहनों की काफी मांग रहने की उम्मीद है। फैंसी कट रत्नों के साथ पारंपरिक और प्राच्य लुक वाले आभूषण होंगे। कुंदन मीना ज्वैलरी के इस साल भी आकर्षण बने रहने की उम्मीद है। हल्के वजन और कलर स्टोन्स के अभिनव प्रयोग से आभूषणों के कई किफायती आईटम्स देखने को मिलेंगे।

जेजेएस में सोशल मीडिया

महावीर पी शर्मा ने बताया कि जयपुर ज्वैलरी शो की एक समर्पित सोशल मीडिया टीम है। इस टीम द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संभावित कंज्यूमर्स तक कम लागत में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवायेंगी। कंज्यूमर्स से जुड़ाव इस रणनीति की प्रमुख विशेषता है, जहां एग्जीबिटर्स के साथ सीधे वार्ता करने की ग्राहकों की नयी भूमिका देखने को मिलेगी। माहौल में विश्वास एवं पारदर्शिता के चलते बिज़नेस कन्वर्जन की दर में इज़ाफा होगा।टीम का मिशन मात्र फेसबुक पर अधिकतम लाइक्स प्राप्त करना और ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या को बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि टीम का ध्येय यह जानकारी देना भी है, जो एग्जीबिटर्स द्वारा किसी प्रोडक्ट की दिलचस्पी में निहित होती है। सोशल मीडिया की बढती लोकप्रियता के चलते इसके माध्यम से ग्राहकों को एक समृद्ध और आकर्षक अनुभव मिलेगा। सोशल मीडिया समय की मांग है, जहां प्रदर्शकों को खुद को व्यवसाय में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को एक समृद्ध और आकर्षक अनुभव होगा।

जयपुर ज्वैलरी डिजाइन फेस्टिवल (जेजेडीएफ)

डॉ. नवल अग्रवाल ने बताया कि डिजाइनरों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए, जयपुर ज्वैलरी शो इस वर्ष 7वीं बार जयपुर ज्वैलरी डिजाइन फेस्टिवल (जेजेडीएफ) की मेजबानी कर रहा है, जिसका थीम 'ट्रेडिशन मीट्स इनोवेशन..रूबी रिडिफाइंड' है।

लगभग 500 वर्गफीट क्षेत्र में फैले इस फेस्टिवल में प्रख्यात ज्वैलरी डिजाइनर ब्रांड्स द्वारा प्रोडक्ट प्रदर्शन, कलात्मक रूप से जेमस्टोन प्रदर्शित करने के लिए एक आर्ट गैलरी, सेमिनार्स, पैनल डिस्कशन, ज्वैलरी का वर्चूअल डिस्प्ले, आदि सहित अनेक प्रकार की गतिविधियाँ होंगी। फेस्टिवल का स्वरूप देने के लिए यहां लाइब्रेरी, कैफेटेरिया और लाइव म्यूजिक भी होगा।

इस साल जेजेडीएफ 8 से 10 प्रमुख डिजाइनिंग संस्थान के छात्रों को मंच देगा, जहां ये नवोदित डिजाइनर अपनी रचना प्रदर्शित कर सकेंगे। यह जेजेडीएफ 2024 प्रमुख डिजाइन संस्थानों से उभरते डिजाइनरों की भागीदारी के साथ-साथ कारीगरों और डिजाइनरों के माध्यम से जयपुर की रचनात्मकता का प्रदर्शन करेगा।

बेस्ट बूथ ट्रॉफी

सुधीर कासलीवाल ने बताया कि जेजेएस में इस वर्ष एक और पुरस्कार श्रेणी को जोड़ा गया है, जिसके तहत 9 वर्ग मीटर की प्रथम और द्वितीय सर्वोत्तम बूथों को पुरस्कृत किया जाएगा।

विजिटर्स के लिए पार्किंग, शटल और मेडिकल सुविधा

सुधीर कासलीवाल ने बताया कि शो में आने वाले विजिटर्स की सुविधाओं एवं सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी विजिटर्स एवं एग्जीबिटर्स के शो में आवागमन के लिए अम्बेडकर सर्किल, वेदा पाणी ग्रह से निशुल्क शटल सुविधा की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, शो के दौरान मेडिकल, एम्बुलेंस एवं दमकल के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं।

जेजेएस का पर्यावरण सुरक्षा में योगदान

मनुज गोयल ने बताया कि जेजेएस का पर्यावरण सुरक्षा के प्रति हमेशा से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी दिशा में, इस वर्ष शो की ब्रांडिंग के लिए कैनवास का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, जेजेएस में इस वर्ष पैट बोटल क्रशर मशीन भी लगाई जाएगी, जिससे प्लास्टिक की बोतलों को तुरंत नष्ट किया जा सकेगा और उनके ग्रैन्युल्स को रीसायकल किया जा सकेगा। इस पहल से प्लास्टिक कचरे के निस्तारण में मदद मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण में योगदान होगा।

जेजेएस- एक सम्पूर्ण शो नवरत्न कोठारी के अनुसार इस वर्ष भी, जेजेएस हीरे, रंगीन स्टोन्स, कीमती धातुएं - चांदी, सोना, बेस-मेटर कार्विंग और बीड्स के साथ एक सम्पूर्ण शो होगा। इसके अवाला, शो में ज्वैलर्स और जेमस्टोन्स डीलरों, ज्वैलरी संस्थानों, प्रकाशनों को भी अवसर मिलेगा। ज्वैलरी और जेमस्टोन के लिए अलग-अलग सेक्शन होंगे। यह वर्गीकरण ग्राहकों के लिए उनकी पसंद का उत्पाद ढूंढने के लिए आसान बनाएगा।

वुमन अचीवर्स का सम्मान

डॉ नवल अग्रवाल ने बताया कि जेजेएस में इस वर्ष वुमन अचीवर्स का सम्मान भी किया जाएगा। जिसके लिए काफी विचार-विमर्श करने के बाद 5 महिलाओं का चयन किया गया। जिन्हें जेजेएस के मंच पर सम्मानित किया जाएगा।

भजनलाल सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियां को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कसी कमर

चमकता राजस्थान

जयपुर!(खलील कुरैशी) राजस्थान में भाजपा सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा के आयोजन की तैयारियों को लेकर अलवर उत्तर जिले की बैठक मुंडावर में आयोजित की गई। इस बैठक में ज़िला समन्वयक व अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती, ज़िला अध्यक्ष उम्मेद भाया, पूर्व विधायक अनीता सिंह, ए.सी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशन मेघवाल, पूर्व प्रदेश मंत्री सुरेश यादव, ज़िला महामंत्री महासिंह, और अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।इस बैठक में जनसभा की सफलता को लेकर रणनीतियाँ बनाई गईं, और आगामी कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया।

ई डी की प्रताड़ना से व्यापारी परिवार का सुसाइट चिंताजनक : गहलोत

चमकता राजस्थान

जयपुर 14 दिसंबर। राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर मध्य प्रदेश में ई डी के अधिकारियों की प्रताड़ना से परेशान होकर एक व्यापारी दंपति द्वारा सुसाइड की घटना बेहद चिंतित करने वाली है। गहलोत ने लिख की सुसाइड नोट में व्यापारी ने लिखा कि लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इनके बच्चों द्वारा शामिल होने एवं अपनी गुल्लक उन्हें देने के बाद से ही उन्हें प्रताड़ित किया जारहा था।

उन्होंने लिखा कि यह विडंबना है कि केन्द्र सरकार संसद में संविधान पर चर्चा करते हुए बड़ी-बड़ी बात कर रही है और दूसरी तरफ आम लोगों को जांच एजेसिंयों द्वारा विपक्षी पार्टी का समर्थन करने पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने जैसी बातें सामने आ रही हैं। यह एक गंभीर मामला है। ई डी क्या अब सीधे ही भाजपा के लिए काम करने लग गई है?

इस घटना से लगता है कि सरकार केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से आम नागरिकों में डर का माहौल पैदा करना चाहती है। उन्होंने लिखा कि ऐसी घटनाएं इतिहास में हुई तानाशाही की घटनाओं की याद दिलाती हैं जहां आम जनता का सरकार का विरोध करने पर ही सेना, पुलिस, इंटेलिजेंस और तमाम सरकारी एजेसिंयों द्वारा दमन किया गया था।

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा कि देश की जनता को सोचना चाहिए कि ऐसी घटनाओं के बाद देश में लोकतंत्र का क्या भविष्य रहेगा?

भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में चहुंमुखी विकास की परिकल्पना को किया जमीनी स्तर पर साकार

चमकता राजस्थान

जयपुर (खलील कुरैशी) 14 दिसंबर। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले एक वर्ष के कार्यकाल में ही कई ऐतिहासिक फैसले एवं काम करके प्रदेश और समाज के सभी पहलुओं के विकास की परिकल्पना को साकार किया है।राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार हर नागरिक के स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, और आध्यात्मिक विकास को महत्व दे रही है और इस दिशा में सरकारी तंत्र को अधिक सक्षम और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के किए सतत प्रयासों से प्रदेश त्वरित गति से प्रगति कर रहा है और नागरिक उज्ज्वल भविष्य के प्रति आश्वस्त हैं। इन्हीं प्रयासों को और अधिक ऊर्जा प्रदान करते हुए प्रदेश के नागरिकों ने अपने समर्थन से भजनलाल की सरकार को और सशक्त बनाया है।आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रदेश के नागरिकों के प्रति अपनी तत्परता प्रदर्शित करते हुए वर्तमान सरकार ने सर्वप्रथम पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत प्रदान की वहीं वह बिजली प्रबंधन में सुधार कर बेतहाशा बढ़ रही विद्युत दर पर लगाम लगाने में भी सफल रही।मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप घरों और कल कारखानों में गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित की है। इससे जहां आम नागरिक को फायदा पहुंचा वहीं प्रदेश में उद्योगों के विकास से रोजगार भी बढ़ा। इस क्रम में विद्युत उत्पादन को बढ़ाकर प्रदेश अब इलेक्ट्रिसिटी डिफिशिएंट से सरप्लस बनने के लिए प्रगतिशील है।गत एक वर्ष में ही प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए पीजीसीआईएल के साथ 10 हजार करोड़ के कार्यों पर सहमति स्थापित की गई है। कोल इंडिया के साथ 3240 मेगावाट और 4340 मेगावाट के लिए कैप्टिव कोयले की आपूर्ति के अनुबंध किए गए हैं। इसके साथ ही गेल, एससीसीएल और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौते किए गए। वर्षों से बंद पड़ी उत्पादन इकाइयों को पुनः शुरू किया गया। 220 केवी के 2 जी एस एस तथा 132 केवी के 19

जी एस एस स्थापित किए गए। इन के साथ ही अन्य बहुत से प्रयास किए गए हैं। इनके परिणाम स्वरूप प्रदेश में बिजली खरीद की औसत दर में 44 पैसे प्रति यूनिट की कमी आई है जिससे बिना उपभोक्ता पर अतिरिक्त भार डाले विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है।ऊर्जा प्रबंधन के साथ ही अन्य आधारभूत सेवाओं को भी सुदृढ़ करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता रही है। इनमें जल प्रबंधन की दिशा में ईआरसीपी के क्रियान्वन में प्रगति से प्रदेश के 21 जिलों के लाखों निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं अपने संकल्प पत्र के अनुरूप सरकार द्वारा ''स्टेट वॉटर ग्रिड'' स्थापित करने के लिए 30 हजार करोड़ की लागत से रन ऑफ वॉटर ग्रिड विकसित किया जा रहा है । यह अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों से पानी को अल्पवृष्टि वाले क्षेत्रों में भेज बाढ़ और सूखा नियंत्रण में प्रभावी होगा। इसके साथ ही पिछले वर्ष में जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर 4722.22 करोड़ रुपए व्यय किए गए। सिंचाई योजनाओं के समयबद्ध विकास के लिए मुख्यमंत्री टास्क फोर्स का गठन किया जाना सरकार की दृढ़ इच्छा प्रदर्शित करता है।

इसी तरह जल जीवन मिशन के अधीन 10 लाख से अधिक परिवारों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। दो लाख 30 हजार से अधिक खराब नलकूपों को सुधार गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त 2000 रुपए प्रतिमाह मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में दिए जा रहे हैं। कृषक को सिंचाई के लिए जल के साथ उचित मात्रा और गुणवत्ता में खाद और बीज उपलब्ध करने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं सर्वांगीण विकास के तहत राज्य सरकार द्वारा 400 से अधिक पीएम विद्यालयों में तीन वर्षीय पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन की पहल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। इससे प्रदेश के भावी नागरिकों में शिक्षा की नींव सशक्त होगी वही उन्हें बेहतर उच्च शिक्षा के लिए 37 नए महाविद्यालयों की स्थापना की गई है, 33 जिला मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों पर इइअ और कंप्यूटर साइंस जैसे समसामयिक कोर्स स्वीकृत किए, सात संभाग मुख्यालयों पर स्थिति महाविद्यालयों में एमबीए, बीसीए और एमसीए स्वीकृत किए गए। 12 महाविद्याय यूजी से पीजी में क्रमोन्नय किए गए हैं।स्वास्थ्य शिक्षा की दिशा में भी प्रदेश ने प्रगति की है और गत वर्ष प्रदेश में 500 से अधिक मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में विशेषज्ञों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए सरकार ने हाइएस्ट लेवल और ट्रीटमेंट फैसिलिटी स्थापित करने के लिए कदम बढ़ाए हैं और एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट और मेडिकल साइंस स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर उपचार आदि जटिल प्रक्रियाओं में भी क्षमता विस्तार के लिए विभिन्न कार्ययोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इस के साथ ही आयुर्वेद उपचार के लाभ उपलब्ध कर नागरिकों के स्वस्थ और सशक्त जीवन के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ।

आधारभूत सुविधाओं के सशक्तिकरण के साथ प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रही है। इस सरकार द्वारा जहां पूर्व में हुई भर्ती घोटाले के दोषियों पर सख्ती से कार्यवाही की गई वहीं एंटी गैंग टास्क फोर्स और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स स्थापित कर अपराध और नशे से प्रदेश के युवाओं के भविष्य की रक्षा की जा रही है। 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के गठन के प्रथम चरण में 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और तीन महिला बटालियन की स्थापना से प्रदेश की माताओं और बेटियों को सुरक्षा और शक्ति मिली है। इन प्रयासों के अनुरूप महिला और दलित वर्ग के विरुद्ध अपराध ने व्यापक कमी आई है (10.18 और 14.28 क्रमश) । इसके साथ ही लोक अदालतों के माध्यम से एक करोड़ से अधिक मामलों का निस्तारण होने से प्रदेश के नागरिकों को राहत मिली है।इनके साथ ही बाल कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और अन्य विभागों में किए प्रयासों से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। प्रदेश के उन्नत भविष्य को और अधिक गति देते हुए राइजिंग राजस्थान का सफल आयोजन भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है।किसी प्रदेश सरकार द्वारा अपने कार्यकाल की शुरुआत में निवेशोत्सव का आयोजन एक नई पहल है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस पहल से निवेशकों का अपूर्व विश्वास प्राप्त हुआ है। ऊर्जा, खनन, उत्पादन, वाणिज्य आदि क्षेत्रों में लाखों करोड़ के निवेश से प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की राह आलोकित हुई है वहीं प्रदेश के युवाओं की उद्यमिता को भी बल मिला है। गत वर्ष हुए इन सहस्त्रों प्रयासों से राजस्थान और सशक्त हुआ है वहीं विश्वास सुदृढ़ हुआ है कि शर्मा के नेतृत्व में सुनहरे धोरों का प्रदेश एक नए स्वर्णिम भविष्य के प्रति प्रगतिशील है।

संक्षिप्त समाचार

प्रदेश में पिछले एक वर्ष में स्थापित हुए विकास के नए आयाम : जोराराम कुमावत बाड़मेर जिला प्रभारी मंत्री

चमकता राजस्थान। जयपुर!(खलील कुरैशी) 14 दिसंबर। पशुपालन मंत्री एवं बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री जोरा राम कुमावत ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जिला परिषद सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान यह बात कही। इस दौरान प्रभारी मंत्री समेत अन्य अतिथियों ने बाड़मेर जिला विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया।बाड़मेर प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित राजस्थान की दिशा में बेहतरीन प्रयास कर रही है। पिछले एक वर्ष में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों, युवाओं, महिलाओं के साथ समस्त वर्गों को राहत प्रदान की गई है। रोजगार उत्सव के माध्यम से युवाओं को नियुक्ति प्रदान कर सौगात प्रदान की गई है। प्रभारी मंत्री ने राज्य सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया गया है। पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगी है और जो पूर्व में पेपर लीक हुए थे। उन पर सख्त एक्शन किया जा रहा है। पुलिस को मजबूत करने की कोशिश की जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री कुमावत ने कहा कि प्रत्येक जिले के पांच गौरव चिन्हित किए गए हैं और उनको बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। बाड़मेर जिले में भी कई महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए डबल इंजन सरकार लगातार कार्य कर रही है, जिससे आमजन का जीवन स्तर सुधारा जा सके।

- **जिला विकास पुस्तिका का विमोचन**

बाड़मेर जिला परिषद सभागार में प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत, विधायक आदूराम मेघवाल, डॉ. प्रियंका चौधरी, जिला कलक्टर टीना डाबी, पुलिस अधीक्षक नरेंद्रसिंह मीना, विश्वकर्मा बोर्ड के अध्यक्ष राम गोपाल सुथार ने जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं एवं बाड़मेर जिले में हुए विकास कार्यों को संकलित किया गया है।

- **प्रचार सामग्री का वितरण**

पत्रकार वार्ता के दौरान सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की ओर से विभिन्न विभागों की ओर से संचालित योजनाओं एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों से संबंधित पोकेट बुकलेट, ब्रोशर एवं अन्य प्रचार सामग्री का वितरण किया गया।

- **जिला विकास प्रदर्शनी का अवलोकन**

बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने जिला विकास प्रदर्शनी एवं पंच गौरव का अवलोकन किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री कुमावत ने कहा कि विकास प्रदर्शनी में राज्य सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी रंगीन छायाचित्रों के साथ प्रदर्शित की गई है। उन्होंने कहा कि सभी जिलेवासियों को इस प्रदर्शनी का अवलोकन करना चाहिए। इस विकास प्रदर्शनी में बजट घोषणाएं, चल रहे कार्य, उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस दौरान विभिन्न जन प्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहें।

सरकार के एक साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर महिला सम्मेलन का हुआ आयोजन

चमकता राजस्थान

जयपुर, (खलील कुरैशी) 14 दिसंबर। राजस्थान सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्षय में जिले स्तरीय महिला सम्मेलन कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर शनिवार को आयोजित किया गया। जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा की अध्यक्षता में आयोजित हुई समारोह में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं को लाभांवित किया गया। सम्मेलन में मेघावी छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया गया वहीं, महिलाओं को सोलर इंडक्शन का भी वितरण किया गया।जिला प्रमुख रमादेवी चोपड़ा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने महिलाओं की बेहतरी के लिए कई फैसले लिये हैं ताकि आधी आबादी प्रदेश के विकास में पूरी भागीदारी निभा सके। महिलाएं प्रदेश की विकास यात्रा में अपना योगदान दे सके इसी दिशा में केन्द्र व राज्य की डबल इंजन की सरकार द्वारा महिला वर्ग को केन्द्र बिन्दु मानते हुए जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी के साथ ही राज्य सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं आत्मनिर्भर बनती है तो राज्य और देश भी आत्मनिर्भर बनता है। राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम एवं बच्चियों व महिलाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए हमने राज्य में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के गठन का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के संचालन के लिए हमने स्वीकृति जारी कर एक हजार कांस्टेबल के पद स्वीकृत कर दिए हैं। महिलाओं को आपात स्थिति में 24 घंटे पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए आज हमने एक ऐप तथा आरएसआरटीसी के सुरक्षा कमांड सेंटर व पैनिक बटन परियोजना का शुभारंभ किया है।आयोजन में जिला कललक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी प्रतिभा वर्मा,अतिरिक्त जिला कलक्टर सुमन पंवार,अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेर सिंह लुहाड़िया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मानसरोवर मीडिया क्लब का हुआ विधिवत उदघाटन

- **वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार फारूक आफरीदी ने क्लब की स्थापना पर प्रेषित करी शुभकामनाएं**

चमकता राजस्थान। जयपुर, 14 दिसम्बर। अँग्रेजी की प्रतिष्ठित पत्रिका ''द वीक'' के रेजीडेंट एडिटर आर. प्रसन्नन ने शनिवार को सायं यहाँ मानसरोवर मीडिया क्लब, जयपुर का फीता काटकर विधिवत उदघाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अमर उजाला प्रकाशन के समूह संपादक डॉ यशवंत व्यास ने की। नगर निगम (ग्रेटर) के उप महापौर पुनीत कर्णावट मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर आयोजित मीडिया और लोकतन्त्र विषयक संगोष्ठी में बोलते हुए आर. प्रसन्नन ने कहा कि पत्रकारिता के सामने हर युग में चुनौतियाँ रही हैं और आज भी हैं लेकिन हमारे जीवट वाले और निर्भय पत्रकारों ने हर स्थिति का मुस्तैदी से उसका सामना किया है और इतिहास इसका साक्षी है। पत्रकारों ने कभी हार नहीं मानी। लोकतन्त्र को बचाने की अपनी ज़िम्मेदारी से हम पीछे नहीं हट सकते। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए तीन युवा पत्रकारों इंडिया टुडे के आनन्द चौधरी, इंडियन एक्सप्रेस की पारुल कुलश्रेष्ठ और दैनिक भास्कर के महावीर शर्मा को एक्सिलेन्स इं जर्नलिज्म अवार्ड से नवाजा गया। कार्यक्रम का संयोजन करते हुए क्लब के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर जयदेव शर्मा ने बताया कि क्लब सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों के साथ साहित्य, कला,संस्कृति, पत्रकारिता और जनसम्पर्क से संबद्ध गतिविधियों और इनके सम्मुनयन के लिए समर्पित रहेगा। वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार फारूक आफरीदी ने क्लब की स्थापना पर हार्दिक बधाई देते हुए अपनी ओर से 100 पुस्तकें भेंट करने की घोषणा की। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ पत्रकार उरुक्रम ने सभी का आभार व्यक्त किया।क्लब के उदघाटन और संगोष्ठी में जयपुर और देश के कई राज्यों से आये पत्रकार, साहित्यकार और बुद्धिजीवी मौजूद रहे।

दी डीस्ट्रीक्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष पद पर गजेन्द्र सिंह राजावत और महासचिव पद पर नरेंद्र सिंह राजावत हुए निर्वाचित

चमकता राजस्थान

जयपुर (खलील कुरैशी)। प्रदेश की करीब 230 एडवोकेट बार के चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। प्रदेश की कई जिला बार एसोसिएशन के परिणाम शुक्रवार को ही आ गए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वन बार-वन वोट के नियमों के तहत हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर व दी बार एसोसिएशन जयपुर व दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सहित प्रदेश की करीब 230 पंजीकृत

बार एसोसिएशन में 2024-25 के वार्षिक चुनाव के बाद शनिवार को मतगणना शुरू हुई जिसमें गजेन्द्र सिंह राजावत अध्यक्ष और नरेन्द्र सिंह राजावत महासचिव निर्वाचित हुए उल्लेखनीय हैं कि अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राजावत को 967 मत प्राप्त हुए और उनके प्रतिद्वंद्वी संदीप शर्मा को 653 मत मिले तथा महासचिव नरेंद्र सिंह राजावत को 728 मत मिले एवं मनोज वर्मा को 617 मत मिले इस दौरान जीत के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राजावत ने कहा कि यह जीत टीम के सामूहिक प्रयास की जीत है निश्चित रूप से आगामी दिनों में सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर काम करेंगे और दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर के चहुंमुखी विकास और अधिवक्ताओं के हितों के लिए जमीनी स्तर पर काम करेंगे इस मौके पर गजेन्द्र सिंह राजावत समेत दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर के निर्वाचित सभी उम्मीदवारों को अधिवक्ता साथियों ने माल्यार्पण कर गर्मजोशी से बधाई प्रेषित करी

जयपुर स्थापना समारोह के तहत पत्रिका गेट पर सिंफनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया

ग्रेटर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर आयुक्त रुक्मणी रियाड, दुर्गेश नंदिनी सहित कई गणमान्य हुए शामिल

चमकता राजस्थान

जयपुर !(खलील कुरैशी) स्थापना समारोह के तहत पत्रिका गेट पर सिंफनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महापौर डॉ सौम्या गुर्जर आयुक्त रुक्मणी रियाड,सांस्कृतिक समिति की अध्यक्ष दुर्गेश नंदिनी, सहित समितियो के

अध्यक्ष एवं पार्षदो ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत ?पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट एवं सलिल भट्ट की जुगलबंदी से पधारो मेरे देश ?से की गई। इस दौरान प्रसिद्ध कलाकार सुजात हुसैन खान द्वारा दी गई अद्भुत प्रस्तुति ने सभी उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में महापौर सौम्या गुर्जर ,आयुक्त रुक्मणी रियाड ने पत्रिका गेट पर मौजूद दर्शकों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई ।

संक्षिप्त समाचार

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का ताज फिर एक बार महेंद्र शांडिल्य के सर पर और महासचिव पद पर रमित पारीक हुए निर्वाचित

चमकता राजस्थान। जयपुर (खलील कुरैशी)। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वन बार-वन वोट के नियमों के तहत हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर व दी बार एसोसिएशन जयपुर व दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सहित प्रदेश की करीब 230 पंजीकृत बार एसोसिएशन में 2024-25 के वार्षिक चुनाव के बाद शनिवार को मतगणना हुई। इस चुनाव में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर लगातार तीसरी बार महेंद्र शांडिल्य चुनाव जीते। वहीं महासचिव पद पर रमित पारीक विजयी रहे। जीत के बाद पत्रकारों से रुबरु होते हुए अध्यक्ष शांडिल्य ने अपनी पुरी टीम और राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं एक ही बात कहूंगा, वकालत करो और दबंगता से सिर्फ वकालत करो, कोई राजनीति नहीं। रिजल्ट की घोषणा होने के बाद शांडिल्य के समर्थकों ने उनका स्वागत किया और बाद में विजयी जुलूस निकाला। अध्यक्ष पद पर महेंद्र शांडिल्य को मिले 1664 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राजीव कुमार को 1453 वोट मिले। महासचिव पद पर रमित पारीक को 1480 वोट मिले। उपाध्यक्ष के दो पदों पर बाबूलाल शर्मा और वंदना शर्मा की जीत हुई। संयुक्त सचिव पद पर सौरभ दुबे, कोषाध्यक्ष पद पर गोविंद शर्मा और सांस्कृतिक सचिव पद पर सुनीता मीणा जीतीं।

बाल्मीकि समाज बस्ती में बस्ती में भारत माता पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ

चमकता राजस्थान /रमेश मोदी। चौमहला /झालावाड़। सेवा भारती भवानी मंडी के तत्वाधान में कस्बे की बाल्मीकि समाज बस्ती में भारत माता पूजन का आयोजन किया गया , कार्यक्रम की अध्यक्षता शंकर लाल वर्मा ने की मुख्य अतिथि कान्हा राठौर, संजय जैन, विष्णु पोरवाल , विशिष्ट अतिथि, विक्रम प्रजापत, ब्रजेश शर्मा, रितेश रहे , कार्यक्रम में बस्ती की सभी माताएं बहने अपने घरों से दीपक लेकर आई बड़ी संख्या में बस्ती के लोग उपस्थित रहे प्रकल्प शिक्षिका स्वाति दुबे ने कार्यक्रम का संचालन किया , मुख्य वक्ता प्रान्त छात्रावास प्रमुख दुलीचंद ने बताया की हमारा भारत बहुत विशाल देश हुआ करता था जिसकी सीमाएं उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के हिंद महासागर तक भारत की सीमाएं हुआ करती थी पर जहां-जहां हिंदू समाज संगठित नहीं रहा वहां अन्य देश बनना प्रारंभ हो गए पर यह जितने भी देश आज भारत से अलग हुए वह कोई भी देश शांत नहीं है जैसे अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल ,भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान ,तिब्बत, श्रीलंका आदि आज अनेक देशो के बीच युद्ध चल रहा है वे सभी भारत की भूमिका की ओर देखते हैं अनेक देश पुन भारत में मिलना चाहते हैं बहुत जल्दी भारत अखंड होगा तहसील अध्यक्ष संजय भंडारी ने सभी का आभार व्यक्त किया भारत माता की आरती कर प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया।

राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ

हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार ने पहले ही साल में कई बड़े निर्णय लिए: राज्यवर्धन सिंह राठौड़ दौसा जिला प्रभारी मंत्री

चमकता राजस्थान

जयपुर, (खलील कुरैशी) 14 दिसम्बर। दौसा जिला प्रभारी तथा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार प्रदेशवासियों से की गई सभी 'गारंटियां' पूरी करने के लिए तीव्र गति से कार्य कर रही है। प्रदेश में विकास की गति को तेज करने और लोक कल्याण के हित में राज्य सरकार ने पहले ही साल में कई बड़े निर्णय लिए हैं, जिससे हर क्षेत्र में खुशहाली परिलक्षित हो रही है। कर्नल राठौड़ शनिवार को यहां दौसा जिला कलक्ट्रेट सभागार में वर्तमान राज्य सरकार के एक साल का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर पत्रकारों के साथ वार्ता कर रहे थे।प्रभारी मंत्री कर्नल राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'नदी जोड़ो' योजना के तहत महत्वाकांक्षी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) का शीघ्र शिलान्यास होगा, जिससे प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल, सिंचाई और उद्योग के लिए जरूरी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। इससे दौसा जिले के भी सभी शहरों और गांवों को फायदा मिलेगा। इस योजना पर करीब एक लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें राज्य सरकार को सिर्फ 10 फीसदी ही वहन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की निरन्तर प्रभावी मॉनिटरिंग की वजह से ईसरदा बांध परियोजना का काम अगले साल पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे दौसा जिले के निवासियों को समुचित गुणवत्तायुक्त पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा उन्होंने कहा कि राज्य में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले नौजवानों के भविष्य पर प्रश्न चिह्न लग गया था। नई सरकार ने आते ही ऐसे अपराधों के खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरु कर युवाओं में पुनः विश्वास बहाल किया है। इस सरकार के कार्यकाल में न केवल प्रतियोगी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो रही है, बल्कि गत सरकार के कार्यकाल में हुए पेपर लीक प्रकरणों में सबूत एकत्रित कर कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहली वर्षगांठ पर 76 हजार 617 नई वैकेंसी की घोषणा की है, जो पूर्ण पारदर्शी तरीके से भरी जाएगी।कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश अनुकूल माहौल तैयार कर औद्योगिक विकास के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार के पहले ही साल में 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' कराना एक दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतीपूर्ण भी था, जिसका शानदार एवं सफल आयोजन किया गया। इससे राज्य में निवेश आएगा और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन और केन्द्र सरकार के साथ विमर्श कर 10 नई नीतियां लाई गई है। इससे नियमों में स्पष्टता आने से निवेशक बिना किसी शंका के राज्य में निवेश कर सकेंगे। केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इन नीतियों को दूसरे राज्यों के लिए नजीर बताया है। उन्होंने कहा कि हर जिले के उत्पादों और हूनर को देश-दुनिया में प्रोत्साहित करने के लिए 'एक जिला, एक उत्पाद' पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा हर जिले की खासियतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 'पंच गौरव' की संकल्पना लाई गई है, जिसके तहत उनके प्रोत्साहन के लिए आधारभूत एवं नीतिगत मदद की जाएगी। इसके लिए दौसा जिले में एक उत्पाद के रूप में सिकन्दरा स्टोन ऑर्टिकल, एक उपज के रूप में सौंफ, एक प्रजाति के रूप में ढाक, एक खेल के रूप में फुटबॉल व एक गंतव्य के रूप में मेहन्दीपुर बालाजी मंदिर का चुनाव किया गया है।

- **इन उपलब्धियों को किया रेखांकित**

प्रभारी मंत्री ने राज्य सरकार की ओर से एक साल में विभिन्न क्षेत्रों में अर्जित उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि 'किसान सम्मान निधि' की राशि प्रति परिवार 2 हजार रुपए बढ़ाकर काश्तकारों को 650 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक वर्ष में 1.25 लाख साइकिल एवं 21 हजार स्कूटियों का वितरण किया गया। पांच नए मेडिकल कॉलेज चालू किए गए। चार हजार स्कूलों में आठ हजार स्मार्ट क्लास रूम तैयार कराए गए। तीन लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया। जल जीवन मिशन के तहत 10 लाख से अधिक नल कनेक्शन किए गए। उज्जवला योजना में 68 लाख परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 14 हजार 500 करोड़ रुपए व्यय कर 20 हजार किलोमीटर सड़कों का कार्य कराया गया। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जा रहा है।

- **कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए**

उन्होंने कहा कि अपराध पर लगाम लगाकर आम नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार बनते ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठित कर कुख्यात गैंगस्टरों को पकड़ने की कार्रवाई की गई। साइबर सुरक्षा के लिए अभियान चलाकर साइबर अपराध पर रोक लगाने में कामयाबी हासिल की है।

- **दौसा जिले ने उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की**

जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि दौसा जिले की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति एवं दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे की वजह से विकास का सबसे ज्यादा लाभ दौसा को होगा। यहां आगामी चार साल में बड़े स्तर पर विकास कार्य होंगे। दौसा जिला आईटी, लॉजिस्टिक, विनिर्माण एवं स्किल सेंटर का हब बनकर उभरेगा।

- **दौसा जिला विकास पुस्तिका का विमोचन**

इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा ने जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में पिछले एक साल में जिले में हुए विकास कार्यों, विशेष नवाचारों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों दर्शाया गया है।

पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने लोहावट ग्राम पंचायत का किया औचक निरीक्षण

ग्राम विकास अधिकारी को एपीओ करने के दिये निर्देश

चमकता राजस्थान

जयपुर!(खलील कुरैशी) 14 दिसंबर। फलोदी जिले के दौरे पर आए शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार देर शाम जोधपुर लौटते समय ग्राम पंचायत लोहावट का आकस्मिक निरीक्षण किया। दिलावर ने पूरे गांव का निरीक्षण किया एवं जगह-जगह गंदगी के ढ़ेर देखकर गहरी नाराजगी जताई। ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचकर पंचायती राज मंत्री दिलावर ने सबसे पहले शौचालय का निरीक्षण किया। शौचालय पूरी तरह क्षतिग्रस्त मिले। जिस पर सरपंच ने बताया कि चोरों ने इन्हें तोड़ दिया। इसके बाद पंचायती राज मंत्री दिलावर ने ग्राम विकास अधिकारी भूराराम चौधरी को बुलाने के निर्देश दिए। सहायक ग्राम विकास अधिकारी ने उसे फोन किया परन्तु वे मौके पर नहीं पहुंचे। इस पर मौके पर उपस्थित अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ने अलमारी का ताला तोड़ कर कार्यवाही रजिस्टर लाने को कहा परन्तु ग्राम पंचायत के कार्मिक अधिकारी कर्मचारी मंत्री को संतुष्टीपूर्ण जवाब देने में विफल रहे। इस पर दिलावर ने ग्राम विकास अधिकारी भूराराम चौधरी को राजकीय कार्य में लापरवाही करने पर तत्काल प्रभाव से एपीओ करने के निर्देश दिए।

प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने 18 दिव्यांगजन को स्कूटी का वितरण कर, हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

कई योजनाओं के लाभान्वितों को बांटे चैक

चमकता राजस्थान

जयपुर (खलील कुरैशी) प्रभारी मंत्री खर्रा ने 18 दिव्यांगजन को स्कूटी का वितरण किया। उन्होंने अंबेडकर भवन परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि राज्य सरकार दिव्यांगजन के हितों के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए स्कूटी का वितरण किया जाता है। स्कूटी मिलने पर ये दिव्यांगजन स्वयं का कार्य करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दिव्यांगजनो ने स्कूटी मिलने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्य सरकार व जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन कार्यक्रम के पश्चात जिला स्तरीय सम्मेलन में प्रभारी मंत्री, जिला कलेक्टर, ब्यावर विधायक व मसूदा विधायक ने पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजना से लाभान्वितों को प्रतीकात्मक चैक सौंपे व सम्मानित किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया, उपखंड अधिकारी गौरव बुद्धनिया, निवर्तमान सभापति नरेश कनोजिया, जिला परिषद ऐसीईओ गोपाल मीणा, नगर परिषद आयुक्त दलीप पूनिया, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक नितेश यादव सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।

सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में 7 जनवरी से 13 जनवरी तक सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबाल प्रतियोगिता 2025 का होगा भव्य आयोजन

खेल मानव जीवन का अभिन्न अध्याय, प्रतियोगिता के आयोजनों से खेल प्रतिभाओं को मिलता है सुसज्जित मंचः प्रेम सिंह बाजौर

राजस्थान की खेल प्रतिभाओं ने समय समय पर प्रदेश और देश का मान बढ़ाया:- डॉ. नीरज के पवन

चमकता राजस्थान

जयपुर (खलील कुरैशी) एडहॉक कमेटी भारतीय वॉलीबाल संघ द्वारा सीनियर नेशनल वॉलीबाल प्रतियोगिता दिनांक 07.01.2025 से 13.01.2025 तक एवं प्रशिक्षण शिविर 17.12.2024 से 06.01.2025 तक जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता एवं शिविर हेतु महिला में जयनारायण, रवि कुमार एवं सुमन पुनिया तथा पुरूष में विनोद कुमार चौधरी, प्रवीण कुमार बिश्नोई एवं विनोद चौहान को प्रतिनियुक्त किया जाता है। उक्त प्रतियोगिता के बाद समाप्ति पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।इस संबंध में एसएमएस स्टेडियम में पत्रकार वार्ता समारोह आयोजित किया गया जिसको प्रेम सिंह बाजौर अध्यक्षः राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड, राजस्थान सरकार.डॉ.नीरज के.पवन अध्यक्षः राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर3.बलदेव गोदारा उपाध्यक्षः आयोजन समिति4.भरत सिंहःसचिव, आयोजन समिति.जय नारायण मुख्य प्रशिक्षकः भारतीय महिला टीम.सुरेश मिश्राः अर्जुन अवार्डी ने संबोधित करते हुए आगामी सीनियर राष्ट्रीय पुरुष/महिला वालीबॉल प्रतियोगिता 2025 के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए पत्रकारों से रुबरु हुए इस अवसर पर प्रेमसिंह बाजौर एवं डॉ नीरज के पवन ने अपने वक्तव्य में बताया कि वॉलीबॉल महासंघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों की देखभाल के लिए भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की सिफारिश पर भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा वर्ष 2023 में भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की तदर्थ समिति का गठन किया था।राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का लम्बे समय आयोजन नहीं होने से खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं अन्य वॉलीबॉल के हितकारकों एवं विकास पर काफी असर पड़ रहा है। प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए एक मंच की आवशयकता को समझते हुए और 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखण्ड में होने वाले आगामी 38 वें राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर वॉलीबॉल फैडरेशन ऑफ इण्डिया की एडहॉक कमेटी ने अपने माननीय पदाधिकारियों के परामर्श से दिनांक 7 से 13 जनवरी 2025 को सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता (पुरुष और महिला) आयोजित करने का निर्णय लिया है और इसका आयोजन स्थल जयपुर (राजस्थान) रखा गया है।विभिन्न राज्य वॉलीबॉल संघों के बीच विवाद है और उक्त विवादों से संबधित मामला माननीय न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन है। इसलिए जयपुर में होने वाली आगामी सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन स्पर्धा आयोजित करने के लिए राज्य खेल विभागों एवं राज्य खेल परिषदों से सम्पर्क किया गया है। इसी के तहत राजस्थान टीम के चयन के लिए चयन स्पर्धा का आयोजन 11 दिसम्बर 2024 को सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में किया जा चुका है। इसके लिए ऑब्जर्वर व सलेक्टर एडहॉक कमेटी (वालीबॉल फैडरेशन ऑफ इंडिया) के द्वारा नियुक्त किए गए। जिसमें पुरूष व महिला वर्ग में अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिसमें मुख्यतः पुरूष वर्ग में राहुल कटारिया, संदीप, निखिल, रजत चबरवाल व महिला वर्ग में सरोज पिपलोदा, आयुषी भण्डारी, कविता, प्रीति मिश्रा व गुंजन रानी प्रमुख है।राष्ट्रीय प्रतियोगिता पूर्व प्रशिक्षण शिविर को आयोजन दिनांक 6 जनवरी 2025 तक आउटडोर खेल मैदान व इण्डोर स्टेडियम में रखा गया है।

सीनियर राष्ट्रीय (पुरुष/महिला) वालीबॉल प्रतियोगिता 2025 की मुख्य विशेषताएं

खिलाड़ियों एवं टीमों की संख्या 35 पुरूष वर्ग तीम व 30 महिला वर्ग टीम कुल 1200 खिलाड़ी भाग लेंगे। इनमें से 600 से अधिक खिलाडी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधितत्य कर चुके है। प्रशिक्षण शिविर - राजस्थान टीम में चयनित पुरूष व महिला खिलाड़ियों का राष्ट्रीय प्रतियोगिता पूर्व प्रशिक्षण शिविर सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्थित आउटडोर खेल मैदान व इण्डोर स्टेडियम में दिनांक 6 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। ठहरने की व्यवस्था - सीनियर राष्ट्रीय (पुरुष/महिला) वालीबॉल प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से भाग लेने वाले खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था आयोजकों के द्वारा थी स्टार होटल में करवाई जा रही है। भोजन व्यवस्था - सीनियर राष्ट्रीय (पुरूष / महिला) वालीबॉल प्रतियोगिता में भाग ले रही टीमों, अधिकारियों के नाश्ते व भोजन की व्यवस्था आयोजकों के द्वारा की जा रही है। लाइव कवरेज सीनियर राष्ट्रीय (पुरुष/महिला) वालीबॉल प्रतियोगिता का लाइव कवरेज किया जाएगा।

नेशनल गेम्स के लिए चयन सीनियर राष्ट्रीय (पुरुष/महिला) वालीबॉल प्रतियोगिता में भाग ले रही विभिन्न राज्यों की टीमों में से सर्वश्रेष्ठ पुरूष व महिला वर्ग की आठ टीमों का चयन 38 वें नेशनल गेम्स 2025 के लिए किया जाएगा।

गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने अलवर में विभिन्न योजनाओं के लाभान्वितों को प्रतीकात्मक चेक सौंपे

डीबीटी से 3581 बेटियों के खाते में पहली किश्त के रूप में करीब 90 लाख रूपये आये

चमकता राजस्थान

जयपुर!(खलील कुरैशी) 14 दिसंबर। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शनिवार को अलवर में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम में गृह एवं गोपालन राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसका एक उदाहरण हाल ही में शुरू हुई लखपति दीदी योजना है जो कि महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कार्य है। उन्होंने कहा कि महिलाएं राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान रखती है वे सरकारी योजनाओं का सकारात्मक रूप से लाभ उठाकर सशक्त बने एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित राष्ट्र व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार बनाएं।

लखपति दीदी, ड्रोन दीदी का किया सम्मान, छात्राओं को सौंपी स्कूटी की चाबी

विभिन्न योजनाओं के लाभान्वितों को प्रतीकात्मक सौंपे चेक एवं लखपति दीदियों का किया सम्मान

जिला स्तरीय कार्यक्रम में लाडो प्रोत्साहन योजना के शुभारम्भ के अवसर पर डीबीटी के माध्यम से 3581 लाभार्थी बेटियों के खातों में प्रथम किश्त के रूप में प्रत्येक बेटी के खातों में 2500-2500 रूपये कुल राशि 8952500 रूपये डाली गई है। इस योजना की 5 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चेक प्रदान किए गए। इसी प्रकार राजीविका द्वारा ही 586 स्वयं सहायता समूह को रिवाॅल्विग फंड के रूप में 80.79 लाख रूपये के फण्ड की सहायता राशि वितरित की गई। अलवर जिले की 10 लखपति दीदियों को मंच पर सम्मानित किया गया एवं रामगढ की गीता समूह की ड्रोन दीदी निशा को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। एक वर्ष के दौरान राजीविका के 2083 समूह के सदस्यों को 61 करोड 87 लाख 40 हजार बैंक के ऋण एवं 3539 राजीविका स्वयं सहायता समूह को 14 करोड 19 लाख 60 हजार रुपए का ऋण राजस्थान महिला निधि बैंक के माध्यम से राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम में जिले के मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत जिले के 1 लाख 49 हजार परिवारों के खातों में डीबीटी से सब्सिडी हस्तांतरित की गई। इलैक्ट्रिक कुकिंग वितरण सिस्टम के तहत 6 लाभार्थियों को इलैक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम प्रदान किए गए।

5 मेधावी छात्राओं को सौंपी स्कूटी की चाबी

अतिथियों ने मेधावी छात्रा स्कूटी योजना व देवनारायण स्कूटी योजना के तहत 5 छात्राओं को स्कूटी की चाबी सौंपी गई जिसमें गोरी देवी महाविद्यालय की छात्रा लिपिका जैन, ईति, आशा बाई, खुशी गुर्जर तथा मॉर्निंग ग्लोरी सीनियर सैकण्डरी स्कूल खेडली की छात्रा कृष्णा राजपूत को स्कूटी की चाबी सौंपी गई। स्कूटी की चाबी पाकर उनके चेहरे खिल उठे।

नए आंगनबाड़ी केंद्र खुले

प्रत्येक विधानसभा में पांच नए आंगनबाड़ी केंद्र का शुभारंभ किया गया है जिसके तहत अलवर जिले में कुल 30 नए आंगनबाडी आज से शुरू हुए तथा प्रत्येक पंचायत समिति में एक आंगनवाड़ी केंद्र को आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा जिसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा मार्गदर्शन पुस्तिका का विमोचन किया गया। इसका भी शुभारम्भ आज किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत प्रथम गर्भावस्था के दौरान पूर्व से निर्धारित 5000 की राशि के अतिरिक्त 1500 की सहायता राज्य सरकार द्वारा दिया जाना प्रारंभ किया गया है जिसके तहत अलवर जिले के 2 हजार 920 लाभार्थियों को 43 लाख 80 हजार रूपये डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए। इस योजना की 5 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक दिया गया। आज से सभी आंगनवाड़ी केंद्र पर मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्किम्ड मिल्क पावडर से तैयार गर्म मीठा दूध सप्ताह में 3 दिन पिलाने का भी शुभारंभ किया गया।

राजीविका की स्टॉल का किया अवलोकन

अतिथियों द्वारा राजीविका की महिला समूहों द्वारा हस्तनिर्मित उत्पादों की लगाई गई स्टॉल का निरीक्षण किया। रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट एकेडमी द्वारा लगाई गई स्टॉल पर सेल्फ डिफेंस का डेमो दिखाया गया। मंत्री श्री बेढम ने सेल्फ डिफेंस का प्रदर्शन करने वाली बेटियों को प्रोत्साहन स्वरूप मिठाई हेतु राशि भेंट की। इस अवसर पर रामगढ विधायक सुखवंत सिंह अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित प्रबुद्ध व्यक्ति, संबंधित अधिकारी एवं लाभार्थी महिलाएं मौजूद थीं।

संक्षिप्त समाचार

रूपवास में अवैध शराब व्यापार से युवाओं में बढ़ रही लत, प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग

चमकता राजस्थान। भरतपुर। भरतपुर/रूपवास। कस्बे के विभिन्न स्थानों पर इन दिनों अवैध शराब का गुप्त कारोबार दिन- ब- दिन बढ़ता जा रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वार्ड नंबर 4 में हाल ही में अवैध शराब की बिक्री में तेज़ी आई है, जिसके कारण युवाओं में शराब की लत तेजी से फैल रही है। इस लत के कारण कई युवाओं की जानें जा चुकी हैं, और उनके परिवारों के जीवन में शोक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

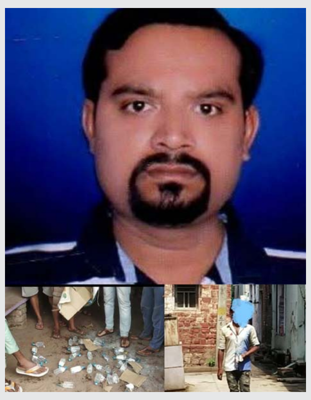

शिकायतकर्ता ने कहा कि महादेव चौक और वार्ड नंबर 4 में 24 घंटे अवैध शराब बेची जा रही है, लेकिन इसके खिलाफ कोई प्रभावी आवाज नहीं उठाता। कस्बे के नागरिकों में प्रशासन और समाज के खिलाफ विरोध करने का साहस खत्म हो चुका है, जिसके कारण इन अवैध कारोबारियों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं।
उन्हें उदाहरण देते हुए बताया गया कि महादेव चौक और वार्ड नंबर 4 में अवैध शराब बेचने वाले तत्वों ने एक युवक, दीपक गर्ग को शराब की लत लगाई, जिसके बाद वह अपनी जान गंवा बैठा। यह घटना न केवल परिवार के लिए एक बड़ी त्रासदी है, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। शिकायतकर्ता ने उपखंड प्रशासन से सख्त अपील की है। कि इन अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं को फिर से होने से रोका जा सके और युवाओं को इस जानलेवा लत से बचाया जा सके। इस मामले में प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और लोगों ने मांग की है कि प्रशासन अवैध शराब की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखे और अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करे, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने मनाया 62 वां स्थापना दिवस 2024

- विद्यार्थियों ने दी रंगारंग एवं मनमोहक प्रस्तुतियां।

चमकता राजस्थान। फुलेरा (दामोदर कुमावत)। पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय फुलेरा में केंद्रीय विद्यालय संगठन का 62 वा स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्राचार्य नरेंद्र सिंह यादव, रहे।इसअवसर पर प्राचार्य ने संगठन के प्रारूप और प्रशासनिक गतिविधियोंपर प्रकाश डाला। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने बढ़-चढ़कर कर भाग लिया और मनमोहक प्रस्तुतियां दी। विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों में केंद्रीय विद्यालय गीत, सामूहिक राजस्थानी लोक नृत्य, सामूहिक पंजाबी लोक नृत्य, सामूहिक नृत्य प्राथमिक एवं माध्यमिक विभाग आदि प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले बच्चों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इसअवसर पर छात्र गिरिराज और विद्यालय शिक्षक हरि सिंह गुर्जर द्वारा भाषण प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर बच्चों का एक मित्रता कबड्डी मैच भी खेला गया। इस मौके पर कार्यक्रमों की एंकरिंग 11 वीं कक्षा की छात्रा निहारिका ने की।

कार की स्टेपनी में छुपा कर तस्करी की 5 किलो 370 ग्राम अवैध अफीम जप्त

चमकता राजस्थान

चित्तौड़गढ़(बाबू अग्नानी)। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध भादसोड़ा थाना पुलिस व जिला विशेष शाखा टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए एक कार से 05 किलो 370 ग्राम अवैध अफीम जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ कार्यवाही करने के जिला पुलिस व डीएसटी टीम को निर्देश दिए गए। इसी क्रम में जिला विशेष शाखा टीम द्वारा दी गई सूचना अनुसार एएसपी सरिता सिंह के निर्देशन व डीएसपी भदेसर अनिल शर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस थाना भादसौडा द्वारा गस्त के दौरान भादसौडा चौराया पर आयी संदिग्ध स्वीफट कार को रूकवाने का प्रयास करने पर कार के चालक द्वारा गाडी को नही रोक भादसौड़ा चौराया से शनिमहाराज रोड भादसोड़ा थाने की तरफ भगा कर गया। जिसका भादसौडा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुये पिछा किया। उक्त संदिग्ध कार का चालक व उसका साथी कार को भगाकर पुलिस थाना भादसौडा से 100 मीटर की दूरी पर गाडी को रोड साईड में झाडियो मे खड़ी कर भागने का प्रयास करने लगे, तभी पुलिस जाब्ता द्वारा घेरा देकर डिटेन किया। उक्त कार व उसके चालक व साथी के पास कोई अवैध मादक पदार्थ होने का संदेह होने से थानाधिकारी शम्भुपुरा ठाकराराम उप निरीक्षक ने मौके पर पहुंच कार की तलाशी ली गई तो कार की डिग्गी के अन्दर स्टेपनी रखने की जगह पर एक बैग में छुपाकर रखी अफीम मिली जिसका मौके पर वजन किया तो अफीम का वजन 05 किलो 370 ग्राम हुआ। उक्त अफीम व कार को जब्त कर कार चालक प्रहलाद पुत्र भैरूलाल जाट उम्र 26 साल निवासी बागुण्ड थाना भादसोडा जिला चितौडगढ व प्रभुलाल पुत्र रामेश्वर लाल जाट उम्र 27 साल निवासी गुढा थाना भादसोडा जिला चितौडगढ को गिरफतार किये गये।

● टीम सदस्य

» हैडकानि. नारायण लाल, सुरेन्द्र सिह, कानि. प्रकाश, सुशील व विरेन्द्र सिंह।

● विशेष योगदान:-

» जिला विशेष शाखा के हैडकानि. मुस्ताक, साईबर सैल के राजकुमार, कानि. रमेश व रोशन जिला विशेष शाखा चितौडगढ।

सीवर और पेयजल लाइन को लेकर कांग्रेस ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

चमकता राजस्थान

धौलपुर रामदास तरुण। बाड़ी। उपखंड के कांग्रेस पदाधिकारियो ने ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा के नेतृत्व में बाड़ी एसडीएम हेमंत कुमार को बाड़ी शहर और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सोपा है। जिसमें कार्रवाई की मांग की है।साथ में कांग्रेसियों ने चेतावनी दी है। कि यदि मांगों को लेकर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा ने बताया कि बाड़ी शहर में वर्तमान में सीवर लाइन और पेयजल पाइप लाइन का काम चल रहा है। दोनों कामों में संबंधित ठेकेदारों द्वारा नियमों की कोई पालन नहीं की जा रही। हालत यह है कि शहर की सड़क जगह. जगह से खुदी पड़ी हैं। नागरिकों को रास्ता निकालने में भी परेशानी हो रही है। जिसको लेकर कई बार नागरिक प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं। लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं दूसरी ओर जिन अधिकारियों को दोनों योजनाओं में मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है। वह कभी भी मौके पर दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में दोनों ठेकेदार मनमानी कर रहे है। यदि यही हालात रहे तो कांग्रेस को आम जनता के साथ विरोध प्रदर्शन आंदोलन करने पर विवश होना होगा। वही दूसरे मांग में कांग्रेसियों ने प्रशासन से आग्रह किया है। कि अठपेरिया गांव से बाड़ी तक लिंक रोड का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। 8 महीने से उक्त मार्ग पर काम नहीं हो रहा। जो काम हुआ है। उसमें भी घटिया सामग्री का उपयोग किया। काफी दिनों बाद विपक्ष ने निभाई पूरा किया जाए। तीसरी मांग में कांग्रेसियों ने बोड़ी शहर से कासोटी खेड़ा भूमिका,, आमजन की परेशानियों को पर बरसात के दिनों में जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। पूरा मागे जर्जर अवस्था में है। देखते हुए हुए दिया ज्ञापन,, जिससे कांसोटी खेड़ा और आसपास क भांव के लोगों को आवागमन में परेशानी नहीं हो। ज्ञापन के दौरान युवक कांग्रेस अध्यक्ष अजय मीणा, अभिषेक यादव, अकरम पठान, धुर्व शुक्ला आदि मौजूद रहे।

कचरोदा श्री श्याम मंदिर प्रबंध कार्यकारिणी गठन

- श्रीशयाम सेवा ट्रस्ट समिति के राजकुमार गुप्ता बने अध्यक्ष।

चमकता राजस्थान। फुलेरा (दामोदर कुमावत)। निकटवर्ती ग्राम काचरोदा स्थित शयाम मंदिर परिसर में श्री शयाम सेवा ट्रस्ट समिति की आवशयक मीटिंग शिवराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई।मीटिंग में ट्रस्ट की स्थाई समिति का पुनर्गठन किया तथा अस्थाई ट्रस्टियों का मनोनयन भी मन्दिर विकास हेतु किया गया। तथा सर्वसम्मती से मन्दिर प्रबन्धकारिणी का गठन किया गया । जो इस प्रकार है। अध्यक्ष-राज कुमार गुप्ता,उपाध्यक्ष शिव राज सिंह राठौड़,मंत्रीसीता राम अजमेरा, संयुक्त मंत्री महेश यादव,उपमंत्री सुरेश चन्द सारस्वत, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण कुमावत,

● कार्यकारिणी सदस्य-

भवरलाल देवतावाल,राम जीलाल पापटवान, जितेद्र अग्रवाल,चेतन बडीवाल व हरिश कुमावत को सर्व सम्मति से बनाया गया।
मीटिंग में निर्णय लिया गया कि श्री शयाम सेवा ट्रस्ट का राष्ट्रीयकृत बैंक में अकाउंट खोला जाएगा तथा नियमित आय के स्त्रोत स्थापित किए जाएंगे। मंदिर व्यवस्था के लिए एक उप समिति का गठन भी किया गया जिसमें संरक्षक हरीश कुमावत, सदस्य कमलेश कुमावत, मनोज कुमावत मंदिर का समय भी पुनर्निर्धारित किया गया प्रातः 5:30 से 12:00 बजे 4:30 से 8: 00 बजे तक किया गया।
अध्यक्ष ने धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि हम सभी को नियमित मंदिर की सेवा की जानी चाहिए।

ग्राम चोसला के ग्रामीणों ने किया भाजपा नेता सुभाष चौधरी का स्वागत

- माइनिंग लीज आवंटन से ग्रामीणों को हुई समस्या का किया समाधान
- अधिकारियों से वार्ता कर लीज का करवाया निरस्तीकरण, ग्रामवासियों के चेहरे पर आई खुशी

चमकता राजस्थान रघुनंदन पारीक /श्रीनगर अजमेर /किशनगढ़। ग्राम पंचायत देवपुरी के ग्राम चौसला में गत दिनों माइनिंग लीज के आवंटन होने पर ग्रामीणों द्वारा विरोध दर्ज करने के साथ ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के आवास पर आकर ज्ञापन सौपकर समाधान करवाने की गुहार लगाई।
जिसपर केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के आवास पर उनके पुत्र भाजपा नेता सुभाष चौधरी ने ग्रामीणों से मुलाकात कर आ रही दिक्कतों को लेकर संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर उक्त माइनिंग के आवंटन को जल्द निरस्त करने हेतु बात रखी, एवं जिसके फलस्वरूप हाल ही में उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया गया, उक्त समस्या का समाधान होने पर चौसला के ग्रामीणो का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को पुनः केंद्रीय राज्य मंत्री एवं अजमेर सांसद के निवास पर पहुँचे ओर सांसद पुत्र भाजपा नेता सुभाष चौधरी का माला साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन कर उनका आभार प्रकट किया। जिसपर भाजपा नेता सुभाष चौधरी ने कहा क्षेत्रवासियों के दुःख दर्द उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में अमरसिंह रायका, शैतान रायका, सोहन, शिवराज, अर्जुन रायका, किशन, जगदीश यादव, कल्याण, घेवर, रतन, भागचंद, हरिराम, घेवर, सोहनलाल, रामचन्द्र सहित सेकड़ो ग्रामीणजन मौजूद रहें।

संक्षिप्त समाचार

अनुसूचित जाति प्रतिभा सम्मान समारोह 29 को होगा

चमकता राजस्थान। धौलपुर रामदास तरुण। धौलपुर सामाजिक जाटव विकास समिति सैपऊ के तत्वावधान में जिला स्तरीय मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में कक्षा 10वीं, 12 वीं बोर्ड परीक्षा 2024 में 80 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी तथा तथा उच्च शिक्षा में यूपीएससी, आरएएस, आईआईटी, एआईआईआईआई, एमबीबीएस 2024 में प्रविष्ट होने वाले छात्र- छात्राओं, 2024 में नवनियुक्त कर्मचारी अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा।
प्रतिभावान अपने कागजात मय आवेदन पत्र के 25 दिसंबर तक जमा करा दें। मेधावी छात्र- छात्राओं को 29 दिसंबर को सैंपऊ रोड स्थित हिना रिसोर्ट में होने वाले कार्यक्रम सम्मानित किया जाएगा।

नेट थिएट पर तबला तालीम

तबले की तिरकिट पर ताले नाच उठी

चमकता राजस्थान। जयपुर। ' नेट थिएट कार्यक्रमों की श्रंखला में आज सुप्रसिद्ध तबला कलाकार पंडित परमेश्वरलाल कथक के निर्देशन में तीन तबलो पर उंगलियों का ऐसा जादू चला की तबले पर एक-एक बोल पर दर्शक वाह-वाह कर उठे '
नेट थिएट के राजेंद्र शर्मा राजू ने बताया की उभरते तबला कलाकार धीरज कथक और पंकज पवार तथा स्वयं पं. परमेश्वर लाल कथक ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत एकहथी पेशकार, चाला उपज कायदा, तिरपली उठान, चक्करदार गत,परन, रेला और लहरी लगी, कवित फरमाइशी मुखड़ा, गणेश परण, कुछ बंदिश अजराहा बनारस, पंजाब, फर्रुखाबाद दिली आदि का कायदा बजाकर लोगों की तालियां बटोरी। इसके बाद सभी ने अपने तबला वादन में मध्यलय में परण, कुछ लय और लगी लड़ी, तिरकिट बजाई और जयपुर घराने की कुछ गते परण पर उंगलियों का ऐसा जादू चलाया कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए '
इनके साथ हारमोनियम पर संगीतज्ञ सांवरमल कथक ने सुरीली संगत से कार्यक्रम को सफल बनाया '
कार्यक्रम का संचालन वायलिन वादक गुलजार हुसैन ने किया '
कार्यक्रम संयोजक नवल डांगी, कैमरा मनोज स्वामी, साउंड मिहिजा शर्मा, मंच सज्जा अंकित शर्मा नोनू एवं जीवितेश शर्मा की रही '

राजाखेड़ा के गांधी चबूतरे मंदिर में भव्य रामायण पाठ और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन

चमकता राजस्थान। धौलपुर रामदास तरुण। राजाखेड़ा 13 दिसंबर 24 को राजाखेड़ा स्थित गांधी चबतरे माता के मंदिर में रामायण पाठ का एक भव्य धार्मिक शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में भाग लिया,जिससे मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। जिसमें पंडित विकास पाराशर ने बताया कि आयोजन के तहत विशेष रूप से रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है,जिसका समापन 15 दिसंबर 2024 को होगा।इस धार्मिक आयोजन में विभिन्न अनुष्ठान,भजन संध्या और पूजा-पाठ का भी आयोजन

किया गया,जिनमें श्रद्धालुओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। वहीं रामायण पाठक कुश राठौर ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य न केवल धार्मिक चेतना का जागरण करना था, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी समृद्ध करना था।आयोजन के आयोजकों का कहना है कि इस तरह के धार्मिक कार्यकलाप क्षेत्रवासियों में आपसी भाईचारे और शांति को बढ़ावा देते हैं।रामायण पाठ और भक्ति गीतों से वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है,जो सभी को एकता और धर्म की शक्ति का अहसास दिला रहा है।इस आयोजन ने क्षेत्रवासियों को धार्मिकता,संस्कृति और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया।इस कार्यक्रम में नत्थीठाकुर,सीताराम गोस्वामी,कुश राठौर,ललित शर्मा,संतोष गुप्ता,पप्पू गिलोचिया,उमाकांत शर्मा,पवन गुप्ता मामा,रजत गुप्ता,सत्यम गुप्ता,ऋतिक, चेतन,अभी,सूरज,कार्तिक, अंजना देवी,अंजलि सहित अन्य भक्तगण मौजूद रहे।

जाजोट कंपनी के एक्सक्लूसिव शोरूम का उद्घाटन।

चमकता राजस्थान। फुलेरा (दामोदर कुमावत)। श्री सिद्ध गणेश मंदिर के समीप सांभर रोड पर शनिवार को जाजोट कंपनी के एक्सक्लूसिव स्टोर का उद्घाटन हुआ। स्टोर प्रोपराइटर सरोज शर्मा पत्नी धनराज शर्मा ने बताया कि इस कंपनी के सी ई ओ शिव दयाल चौधरी स्टेट हेड जय प्रकाश शर्मा एवं सर्विस हेड दीपेश सैनी ने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी में 121 प्रोडक्ट से अधिक आइटम्स बनाए हैं जो रोजमर्रा के जीवन एवं सुख सुविधा के अनुरूप तथा सस्ते दामों में यहां फुलेरा कस्बे आसपास के क्षेत्र के लिए उपलब्ध रहेंगे कंपनी ने सोलर प्रोडक्ट के अलावा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक एवं दैनिक उपयोग के किफायती प्रोडक्ट आपके समक्ष पेश किए हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने स्टोर प्रोपराइटर धनराज शर्मा को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की।पालिकाध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष योगेश सैनी पार्षद प्रति निधि गजेंद्रसिंह शेखावत, ताराचंद सैनी, नेताप्रतिपक्ष संजयपारीक, महावीर जैन,सुबोध छाबड़ा,सत्यम अस्पताल के निर्देशक डॉ.एस के मोंगिया, पुनीत धवन, हिमांशु शर्मा, लोकेश कुमावत,सुरेंद्र स्वामी, सहित गणमान्य लोग उपस्थिति थे।

राज्य में सड़कों की गुणवत्ता को लेकर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी गंभीर

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नाथद्वारा में किया सड़कों का औचक निरीक्षण

लापरवाही पर जेईएन और एईएन को एपीओ करने, एक्सईएन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश

निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की कोताही स्वीकार्य नहीं : उपमुख्यमंत्री

चमकता राजस्थान

राजसमंद 14 दिसंबर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी राज्य में सड़कों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर हैं और निरंतर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि निर्माण कार्यों में लापरवाही न हो। उपमुख्यमंत्री शुक्रवार को नाथद्वारा पहुंची थी और शनिवार को उदयपुर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में भाग लेने से पूर्व उन्होंने सड़कों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम रक्षा पारीक, पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अशोक कुमार शर्मा, अधीक्षण अभियंता मगनीराम रैगर आदि मौजूद रहे।
उपमुख्यमंत्री नाथद्वारा उपखंड क्षेत्र के गुंजोल-कुंचोली मार्ग पहुंची। यहां उन्होंने सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही पाए जाने और काम गुणवत्ता से नहीं होने पर कड़क नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। इस दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अशोक शर्मा को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संवेदक पर कार्रवाई अमल में लाई जाए, जरूरी हो तो ब्लैकलिस्ट करें।

उपमुख्यमंत्री ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचौली के सामने मौके पर ही उदयपुर एक्सईएन क्वालिटी कंट्रोल कार्यालय की क्वालिटी चेकिंग मशीन मंगवाई और सड़क की गुणवत्ता जांची।
सड़क निर्माण में खामियाँ मिलने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता जितेश व्यास और सहायक अभियंता नमित मिश्रा को एपीओ करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिशासी अभियन्ता भानुप्रकाश माथुर को 17 सीसी के नोटिस देने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़कों और अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर पूरी गंभीर है, निर्माण कार्यों में लापरवाही किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। यह अधिकारियों का दायित्व है कि निर्माण कार्यों का निरंतर घंटा से निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी कम गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो। निरीक्षण के दौरान का स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे जिन्होंने निर्माण कार्यों के संबंध में समस्याएं उपमुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की।

श्रीनाथजी के ग्वाल दर्शन कर लिया आशीर्वाद

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निरीक्षण से पहले नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथजी के मंदिर में सुबह 9:15 बजे ग्वाल झांकी के दर्शन किए। इसके पश्चात उनका गोस्वामी विशाल नाथद्वारा (विशाल बावा) ने समाधान पद्धति से स्वागत किया। स्वागत पश्चात विभिन्न विषयों पर उपमुख्यमंत्री और बावा के मध्य चर्चा हुई। इस दौरान कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे।

जयपुर भोपाल जयपुर ट्रेन आज से पुनः जयपुर तक दैनिक रेल यात्री संघ 'एकी' की मेहनत रंग लाई

चमकता राजस्थान

फुलेरा (दामोदर कुमावत)। जयपुर भोपाल जयपुर ट्रेन 19711/19712 को रेल प्रशासन ने 29 नवंबर 24 से 13 जनवरी 2025 तक इस ट्रेन को जयपुर के बजाय कनकपुरा तक ही चलाया जारहा था, जिससे दैनिक रेल यात्री व आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था,इस संबंध में दैनिक रेल यात्री संघ एकीकृत फुलेरा की ओर से मंडल रेल प्रबंधक विकास पुरवार व अपर मंडल रेल प्रबंधक गौरव गौड को ज्ञापन देकर इस विकेट समस्या से तुरंत निजात दिलाकर इस ट्रेन को पुनः जयपुर स्टेशन से ही चलाए जाने की पूरी जोर शब्दों में मांग रखी इस पर रेल प्रशासन

ने दैनिक रेलयात्री संघ 'एकी' की मांग को स्वीकार करते हुए 15 दिसंबर 2024 यानी कल से जयपुर- भोपाल- जयपुर ट्रेन को पुनः जयपुर से ही चालने के आदेश जारी कर दिए हैं
इसके लिए दैनिक रेल यात्री संघ एकीकृत फुलेरा महा प्रबंधक ,मंडल रेल प्रबंधक ,अपर मंडल रेल प्रबंधक संहित रेलप्रशासन को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है।

डॉ. तरुण शर्मा ने नीट पीजी में चयनित होकर सरमथुरा का नाम रोशन किया, भव्य स्वागत

चमकता राजस्थान

धौलपुर रामदास तरुण। धौलपुर उपखण्ड सरमथुरा के विरहरु पाड़ा निवासी डॉ. तरुण शर्मा, पुत्र विष्णु शास्त्री का नीट पीजी में चयन होने पर परिवार और मित्रों ने उनका भव्य स्वागत किया। डॉ. तरुण को एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में जनरल सर्जरी (टर) के पीजी कोर्स में प्रवेश मिला है। आज सर मथुरा लौटने पर उनके परिवार और मित्रों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर डॉ. तरुण के पिताजी विष्णु शास्त्री ने बताया कि डॉ. तरुण ने एमबीबीएस भी एसएमएस जयपुर से 2023 में पूरा किया था, और महाकालेश्वर बाबा की कृपा एवं बड़ों के आशीर्वाद से उन्हें पीजी कोर्स टर में भी एसएमएस

जयपुर में ही चयनित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वागत समारोह में दादाजी रामचरण शर्मा (पूर्व अध्यक्ष ब्राह्मण समाज), किरोरी शर्मा (पूर्व अध्यक्ष ब्राह्मण समाज), दिवाकर शर्मा, अरुण शर्मा, डॉ. रमेश शर्मा, गोविंद चरोरी, डॉ. ब्रजेश उपाध्याय, केके शर्मा, भास्कर उपाध्याय, सतीश बंसल, जितेंद्र जादौन, पवन शर्मा, मुकेश शर्मा, महेश ठेकेदार, सुभाष शर्मा, नीरज स्वामी, विक्की स्वामी, पिंकी लवानिया, राजेश मुद्गल, रोहित शर्मा सहित अन्य ने डॉ. तरुण को पुष्पमाला पहनाकर और साफा बांधकर उनका स्वागत किया। बैंड-बाजा के साथ वे बस स्टैंड से उनके घर तक नाचते-गाते पहुंचे।
इस प्रकार, डॉ. तरुण का चयन न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे कस्बे के लिए गर्व का विषय है।

भजनलाल सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों को निचले स्तर तक लेकर जाये : राजेंद्र राठौड़

नरेंद्र मोदी के आगमन पर घर घर जाकर पीले चावल बांटकर आमजन को सभा में आने के लिए दे निमंत्रण- डॉ. अरूण चतुर्वेदी

चमकता राजस्थान

जयपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर राजस्थान सरकार के 01 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर दिनांक 17 दिसम्बर 2024 को आयोजित होने वाली सभा की तैयारी हेतु जिला जयपुर शहर, जयपुर देहात दक्षिण और जयपुर देहात उत्तर की क्रमवार अलग-अलग बैठकों का आयोजन हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता व कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र राठौड़ और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने बैठकों को संबोधित किया।
बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता व कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के एक वर्ष पूर्ण होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में प्रधार रहे है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि देश के प्रधानमंत्री

का गर्म जोशी के साथ अधिक से अधिक संख्या में प्रधार कर स्वागत करना चाहिए और इस कार्यक्रम को यादगार कार्यक्रम बनाने में सभी का योगदान होना चाहिए।
राठौड़न ने कहा कि कल दिनांक 15 दिसम्बर को तीनों जिलों में मंडल बैठकों का आयोजन करना है जिसमें बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जन जन तक प्रधनमंत्री के आगमन का निमंत्रण देने के लिए प्रोत्साहित करना है।
भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि मोदी जी के आगमन पर घर घर जाकर पीले चावल बांटे और सभी को सभा में आने के लिए निमंत्रण दे। सभी मोर्चा पदाधिकारी विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को जोड़ने का प्रयास करें और भजनलाल सरकार की एक वर्ष की उपल्बधियों को निचले स्तर तक लेकर जाये। मंडल पदाधिकारी सभी बूथों पर जाकर यह सुनिश्चित करे कि हमारा एक -एक कार्यकर्ता एक वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होने वाली सभा में पधार रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करे।
जिला अध्यक्ष राघव शर्मा ने बताया कि जो भी व्यवस्था करी गई है उस के बारे में सभी को बताया और सम्बंधित व्यक्तियों के नम्बर सभी को बताये गये।
बैठक में, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश महामंत्री एवं विधायक जितेंद्र गोठवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, जिला जयपुर शहर अध्यक्ष राघव शर्मा, जयपुर देहात उत्तर अध्यक्ष श्याम शर्मा, जयपुर देहात दक्षिण जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर , विधायकगण, नगर निगम महापौर, उपमहापौर पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, जिला के पदाधिकारी, पार्षदगण और मंडल के अध्यक्ष और पदाधिकारी, विधानसभा संयोजकण उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक अभय सिंह चौहान के लिए एम बी प्रिंटर्स, सी 74 सुदर्शन पूरा, जयपुर से मुद्रित एवं 1ए देवी नगर विस्तार, देवी नगर गली नं. 6 जयपुर 302019 से प्रकाशित। सम्पादक : अभय सिंह चौहान, मोबाइल : 9314505000 (पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार) संपादक : खलील कुरैशी, मोबाइल : 7891542929